जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत
कोटा
Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

कोटा, शनिवार 26 अक्टूबर, 2024

गहलोत सरकार के जाने के ग्यारह महीने बाद अभी भी उस सरकार की बात करने की इतनी उत्कंठा क्यों?

सरकारी तंत्र, सरकारी प्रशासन ''लाइन ऑफ कमाण्ड'' (आदेशों की श्रृंखला) के मार्फत काम करता है। जिला स्तर पर, उदाहरण के लिए पुलिस तंत्र में एस.पी., एडिशनल एस.पी., थानाधिकारी आदि की श्रृंखला होती है। गहलोत ने विधायक को प्रशासन की धुरी बनाकर यह ''लाइन ऑफ कमाण्ड'' तोड़ दिया था और, सभी स्तर के कर्मचारी केवल विधायक की ओर देखने लगे अगले आदेश की प्रतीक्षा में। वरिष्ठता केवल ''अलंकार'' बनकर रह गयी, उसका प्रशासनिक महत्व लगभग खत्म हो गया। इस प्रशासनिक अराजकता से बचने के लिए, पुराने मुख्यमंत्री, कम से कम भैरोंसिंह शेखावत तक, विधायकों की, अफसर की ट्रांसफर-पोस्टिंग की मांग पर दो टूक जवाब देते थे, ''तुम्हारे कहने पर अफसर तो हटा देता हूँ, पर उसकी जगह किसे लगाऊं यह मैं ही निर्णय लूंगा।'' मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार विधायक को ही दे दिया था, इससे प्रशासनिक अराजकता तो फैलनी ही थी। पुराने मुख्यमंत्रियों ने तो प्रशासनिक अराजकता को फैलने से रोकने के लिए कुछ नीतियां-रीतियां बनाईं, लेकिन, गहलोत ने इस अराजकता को सींचने के लिए, पनपाने के लिए, बांध के सब गेट खोल दिये थे। नारा था, प्रशासनिक अराजकता जाए भाड़ में, लेकिन, मेरी सल्तनत सुरक्षित बनी रहे। सरकारी व प्रशासनिक संस्थानों की तोड़-मरोड़ की गूंज ग्यारह महीने बाद भी सुनी जा सकती है। और भ्रष्टाचार के इस पहिए को थमने और पलटने में ना जाने कितने वर्ष लगेंगे।

राजेश शर्मा
प्रधान सम्पादक
राष्ट्रदूत

लगभग साल भर पहले, राष्ट्रदूत ने रॉ के पुराने चीफ, ए.एस. दुलत साहब की नई किताब ''लाइफ इन द शैडोज़'' पर एक ''बुक इवैंट'' (पुस्तक पर गहन चर्चा) आयोजित किया था। दुलत साहब राजस्थान कैडर के आई.पी.एस. अफसर थे, पर अधिकतर दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेन्सियों, जैसे आई.बी., रॉ आदि में ''पोस्टेड'' रहे, अतः उनके लिए आयोजित ''इवैंट'' काफी रोचक व ''पॉपुलर'' रहा, विशेषकर, राजस्थान पुलिस उच्चाधिकारियों में। ''वर्ड ऑफ माउथ'' से इवैंट दिल्ली के ''इन्टैलिजैन्स सर्किल'' में भी काफी चर्चित रहा। दिल्ली के जिमखाना क्लब में मेरी जब भी ''इन्टैलिजैन्स ऑफिसरों'' से मुलाकात व चर्चा हुई, तो उनके सभी पुराने साथियों ने ''दुलत साहब'' की किताब को ''हाइ लाइट'' करने को सतही तौर पर काफी सराहा पर मुझे महसूस हुआ, कि, इस सर्किल में दुलत साहब की किताब को लेकर थोड़ी सी ''अनईज़ीनैस'' (बेचैनी सी) भी है।

रॉ के एक रिटायर्ड वरिष्ठतम अधिकारी से, जिसे कालान्तर में थोड़ा मैं गहराई से जानने लगा, एक शाम को अपनी इस ''अनईज़ीनैस'' के अहसास को मैंने शेयर किया और इस अनईज़ीनैस का कारण जानने की कोशिश की, क्योंकि ''बुक इवैंट'' के बाद मैंने दुलत साहब से बातचीत में पूछा था ''आपने किताब तो बहुत पठनीय व रोचक लिखी, पर कहीं पुस्तक के कारण आप दिक्कत में नहीं आ जाओ, ''ऑफिशियल सीक्रेट्स'' आदि में। दुलत साहब ने एक तरह से ताल ठोकते हुए कहा, मेरे खिलाफ ''ऑफिशियल सीक्रेट्स'' का कोई मामला नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने तो किताब में केवल उन जानकारियों का उल्लेख किया, जो ''पब्लिक डोमेन'' में हैं, (सार्वजनिक तौर पर ''फ्रिली'' उपलब्ध हैं)।

''रॉ'' के अधिकारी ने सकुचाते हुए कहा कि दुलत साहब सही कह रहे हैं, जानकारियां ''फ्रीली'' उपलब्ध तो हैं, पर कहीं भी पुस्तक के रूप में नहीं छपीं। अतः ये जानकारियां, ''संदिग्ध'' सी भी हैं, आम जनता के लिए, कुछ कोहरे से में हैं। पर, दुलत साहब ने, जो हमारे पूर्व चीफ थे, इन्हें पुस्तक के रूप में, छापकर, इन जानकारियों को ''ऑथैन्टिकेट'' कर दिया (सत्यापित कर दिया) सारे कोहरे हटा दिए। यह बात थोड़ी सी ''अनईज़ीनैस'' पैदा करती है।

यही स्थिति ''करप्शन'' के बारे में भी है। शायद अनादिकाल से प्रशासन में, सरकारों में, थोड़ा बहुत करप्शन रहा है। पर सरकार व समाज उस पर ''कम बेसी'' नियंत्रण रखता आया है। पर, समाज को प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाया। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, भ्रष्टाचार को डाइबीटीज़ की भांति ''परमिसेबल लिमिट्स में'' (अहानिकारक परिधि में) तो सीमित रखा जा सकता है, पर प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया जा सकता।

गहलोत के शासन ने इस ''करप्शन'' को सरकारी मान्यता दी, प्रतिष्ठित किया, व्यवस्थित किया, सिस्टम का हिस्सा बना दिया। अफसरों को और सरकारी मशीनरी को यह नारा देकर, कि स्थानीय विधायक ही अपनी ''कॉन्स्टिट्युएंसी'' (चुनाव क्षेत्र) का मुख्यमंत्री है। उसकी ही चलेगी, और सरकारी मशीनरी उस को समर्थन/सहयोग दे। इस नई व्यवस्था में सरकारी ''इन्स्टीट्यूशन'', (प्रशासन) की परम्पराएं शून्य, प्रभावहीन तो होनी ही थीं और यहीं से खाओ और खाने दो की ही नहीं, बल्कि खाना जायज़ है, की व्यवस्था बैठाई गई। यह सिस्टम कैसे बना इसकी डीटेल चर्चा आगे करेंगे, किंतु ''करप्शन'' इतना, बेधड़क, खुल्लम-खुल्ला होने लगा, कि सचिवालय में सरकारी अलमारी में ''रिश्वत'' का सोना व रुपये पकड़े गये, पर जांच की औपचारिकता ही पूरी की गई। ''नैट रिज़ल्ट'', यह विश्वास बन गया, कि इसी व्यवस्था का हिस्सा बनें अन्यथा कर्मचारी का भविष्य नहीं है। । प्रशासनिक ''इन्स्टिट्यूशन्स'' को इतना दीमक लगा कि अब शायद कई दशक लगेंगे, करप्शन को ''परमिसेबल लिमिट्स'' में लाने के लिए। यह ''परमानैन्ट देन'' है गहलोत के प्रशासन की। और, यह ''गिफ्ट'' गहलोत बार-बार देना चाहेंगे। क्योंकि उनके मन में कहीं भी कुछ ग्लानि नज़र नहीं आती कि, उन्होंने राज्य में प्रजातंत्र की जड़ें उखाड़ कर फैंक दी हैं। वे मन से विश्वास करते हैं, कि राजा ही तो राज्य है, अतः किसी भी तरह, राजा को बनाये रखना, सुरक्षित रखना ही ''राजधर्म'' है। उनके मन में शायद एक ही अफसोस है, कि पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाये। वे इसके लिए, रणनीति के क्रियान्वन में कमी को ही हार का कारण मानते हैं। ''करप्शन'' को राज धर्म बनाने के मूल सिद्धांत को कतई बुरा नहीं मानते।

पर, इस विवरण के बाद में भी यह प्रश्न अनुत्तरित सा ही रह गया है, कि अब इस समय उनकी सरकार के जाने के ग्यारह महीने बाद भी निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में बात करने की उत्कण्ठा क्यों है? इस संदर्भ में रामायण का वह प्रसंग स्मरण हो आता है, जब युद्ध के दौरान राम के बाणों की बारिश से घायल होकर रावण मूर्छित हो गया था और उनके सारथी ने उनके रथ को लंका में ले जाने के लिए मोड़ा था, उस समय लक्ष्मण, घायल लंकेश को खत्म करने के लिए तत्पर और तैयार थे। राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा, रावण कोई साधारण शत्रु नहीं है, जिसे जैसे-तैसे भागते हुए घायल तथा मूर्छित अवस्था में मार कर, विजय हासिल करना पर्याप्त है। इसी संदर्भ में राम ने आगे कहा कि यह युद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ा गया है, राज्य पाने के लिए नहीं। रावण अधर्म का प्रतीक है, उसे सबके सामने युद्ध करके और पराजित करके मारना जरुरी है। जिससे यह सदा के लिये साबित हो जाये कि अधर्म के रास्ते पर चलकर फरेब से, छल से, चाहे कोई सोने की लंका तो बना ले, पर इसका अन्त अशुभ और विध्वंसकारी ही होता है। राम के कहने का आशय था कि रावण कोई चिन्दी चोर नहीं था, जिसे रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दण्ड देना पर्याप्त है।

किसी भी मायने में गहलोत भी कोई चिन्दी चोर नहीं थे। अतः उन्हें भी चुनाव में हरा देना काफी नहीं है। उनकी हार पर चर्चा करना जरुरी है, क्योंकि, कई मायनों में तो वह ''युग पुरुष'' थे, जिसने सरकार की, प्रशासन की परिभाषा ही बदल दी, अपने कार्यकाल में।

अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी को ''इन्स्टिट्यूशनलाइज़'' कर दिया। यानी सरकारी सिस्टम का ''जायज़'' हिस्सा बना दिया, यह नारा देकर कि विधायक ही अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री है। ऑन द ग्राउण्ड यह प्रतिलक्षित हुआ, और उसका एक मूल उदाहरण जयपुर के नज़दीक कस्बा-ए-कोटपुतली में देखने को मिला। जहां नैशनल हाई-वे से जुड़ी रोड को ''तथाकथित'' सरकारी मापदण्ड के अनुसार चौड़ा करने और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए लगभग 150 घरों और दुकानों की भारी तोड़-फोड़ की गई। कइयों के पास खेतड़ी राज के पट्टे मौजूद थे, अन्य के पास निगम द्वारा स्वीकृत व पास किये गये नक्शे थे। पर, न्याय के लिए कहाँ गुहार की जाये, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के लिए तो विधायक उस क्षेत्र का ''घोषित मुख्यमंत्री'' था। पीड़ित जनता ने न्यायालय से आदेश प्राप्त किये पर जनता यह भूल गई कि न्यायालय के आदेश भी अंततोगत्वा प्रशासन ही लागू कराता है।

गहलोत के राज के जाने की वजह उनकी सोच, ''फिलॉसफी'' का सुनियोजित, सटीक क्रियान्वन था। अभाव था या कमी थी तो नैतिक मूल्यों की, स्वस्थ प्रजातंत्रीय फिलॉसफी की, जिसमें शासन की धुरी होती है जनता, न कि राजा, क्योंकि, राजा की बेलगाम महत्वाकांक्षा का खामियाज़ा जनता उठाती है और जनता में आक्रोश फैलता है, और इसी आक्रोश की वजह से गहलोत की हार हुई, उनकी सत्ता गई। रावण की भांति, केवल गहलोत को हराना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि हार-जीत तो राजनीति का अंग है। गहलोत की हार उस ''फिलॉसफी'' की हार है, जिसमें जनता केवल एक आंकड़ा होती है, और वो ही जीतता है, जो आकड़ों की गणित का सही ''कॉम्बिनेशन'' (संतुलन) बिठा लेता है। गहलोत की इस ''फिलॉसफी'' की अपूर्णता पर चर्चा करना और असार्थकता बताना जरूरी है। यह ही उस उत्कण्ठा के मूल में है, कि गहलोत के सत्ताच्युत होने के ग्यारह महीने बाद भी गहलोत के बारे में बात करने के लिए बेचैनी रहती है, क्योंकि गहलोत शासन प्रणाली की ''फिलॉसफी'' की दुर्बलता, निर्बलता और कुरूपता को समझे और समझाये बिना गहलोत को केवल चुनाव में हरा देना वैसा ही है, जैसे कि घायल मूर्छित रावण को रात के अंधेरे में मार देना, जिसे राम ने वर्जित किया था। उस वध में, राजा की मृत्यु से जनित अवसाद में, रोने-धोने में, उस समय की मान्यता व सभ्य समाज के तौर तरीकों से परिभाषित अधर्म, पाप-फरेब आदि की अवांछनीयता दब जाती, उभर कर सामने नहीं आती और राम के वनवास का अघोषित उद्देश्य अपूर्ण रहता।

गहलोत जन आक्रोश की आंधी के कारण हार गये, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है, जनता गहलोत द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली को जाने व पहचाने, जिसने हमारे प्रजातंत्र को इतना विकृत बनाया। इतना भयावह व डरावना बनाया।

जिस बेशर्मी से, निर्दयता से, भ्रष्टाचार पनपाया गया, इतनी बेशर्मी, क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई। जायज़-नाजायज़ काम की कुंजी पैसा हो गयी। सरकारी महकमे ''कलैक्शन केन्द्र'' बन गये और हर सक्षम अधिकारी व जनप्रतिनिधि ''कलैक्शन एजेन्ट''। पुरानी लोकोक्ति थी, ''बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है'', पर गहलोत ने तो हर डाल पर चुन-चुन कर हर स्तर पर ''उल्लू'' बिठा दिया, और साथ में ''फ्रीडम'' दे दी कि ''कमाओ और खाओ'' का सिद्धान्त पूर्णतया स्वीकार्य है। डर, इस बात का है, कि हर स्तर पर ''उल्लुओं'' को खून मुंह लग गया है, पांच साल में। अब यह ''सिस्टम'' ठीक होने में कई दशक लगेंगे, और जनता ही इसे ठीक कर सकती है, ''बुद्धिमानों'' का भाषण नहीं। मन में उत्कण्ठा गहलोत के बारे में बात करने की इसलिए रहती है कि, जनता पूरी तरह समझ ले कि ''सिस्टम'' को क्या हानि हुई। क्योंकि गहलोत के सोच व कार्य प्रणाली का एक और अनुभव शायद राजस्थान का प्रजातंत्र नहीं झेल पायेगा।

सन् 1989 की बात है, अशोक गहलोत जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उनके आग्रह पर मैं चुनाव कवर करने जोधपुर गया था। आर.टी.डी.सी. के होटल घूमर में ठहरा था। अशोक गहलोत का मैसेज आया, जोधपुर के उद्योगपति घेवर चन्द कानूनगो ने शहर के बड़े-बड़े व्यापारियों को नाश्ते पर बुलाया है, गहलोत भी रहेंगे, आप भी आईये, अच्छी ''न्यूज़'' मिलेगी। नाश्ते के बाद कानूनगो ने 150-200 बड़े आमंत्रित

रॉ के पूर्व चीफ दुलत साहब की किताब पर पुलिस के उच्चतम क्षेत्र में ''अनईज़ीनैस'' थी, कि उन्होंने वो सब लिख दिया जो लोगों को मालूम तो था पर विश्वसनीयता संदिग्ध थी। किताब ने सब बातों को सत्यापित कर दिया। यही बात ''करप्शन'' को लेकर है। सब जानते थे कि थोड़ा करप्शन तो होता ही है, पर गहलोत ने विधायक को कॉन्स्टिट्युएंसी का मुख्यमंत्री बताकर करप्शन को सरकारी मान्यता दे दी। करप्शन इतना बेधड़क, खुल्लम-खुला होने लगा कि सचिवालय में सरकारी अलमारी में ''रिश्वत'' का सोना व रुपये पकड़े गये, पर जाँच की औपचारिकता ही पूरी हुई।

जिस बेशर्मी से, निर्दयता से, भ्रष्टाचार पनपाया गया, इतनी बेशर्मी, क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई। जायज़-नाजायज़ काम की कुंजी पैसा हो गयी। सरकारी महकमे ''कलैक्शन केन्द्र'' बन गये और हर सक्षम अधिकारी व जनप्रतिनिधि ''कलैक्शन एजेन्ट''।

एक उदाहरण जयपुर के नज़दीक कोटपूतली कस्बे का है। वहाँ ''तथाकथित'' सरकारी मापदण्ड के अनुसार रोड चौड़ी करने के लिए 150 घरों व दुकानों में भारी तोड़फोड़ की गई। कइयों के पास खेतड़ी राज्य के पट्टे मौजूद थे, अन्य के पास नगर पालिका द्वारा स्वीकृत नक्शे थे। पर स्थानीय प्रशासन के लिये विधायक क्षेत्र का ''घोषित मुख्यमंत्री'' था। पीड़ित जनता ने न्यायालय से भी आदेश प्राप्त किये, पर न्यायालय के आदेश भी तो अंततोगत्वा प्रशासन ही लागू करता है।

सन् 1989 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जोधपुर वासी जिस भी काम के लिए कहते, उनका जवाब होता था, ''यह स्थानीय मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बताओ'' तंग आकर एक आदमी ने हज़ार रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा, ''दिल्ली के चांदनी चौक में बाबा छाप ज़र्दे का तम्बाकू मिलता है, अगली बार दिल्ली से आयें तो दो डिब्बे लेते आइयेगा।''

गहलोत के मन में कहीं भी कुछ ग्लानि तक नहीं आती कि उन्होंने राज्य में प्रजातंत्र की जड़ें उखाड़कर फेंक दीं। वे मन से विश्वास करते हैं कि राजा को बनाये रखना ही राजधर्म है। करप्शन को राजधर्म बनाने के मूल सिद्धान्त को वे कतई बुरा नहीं मानते। उनकी सरकार जाने के ग्यारह माह बाद गहलोत के बारे में बात करने की उत्कंठा क्यों है? इस संदर्भ में रामायण का प्रसंग याद आता है। जब मूर्छित रावण को उनका सारथी लंका वापस ले जा रहा था, लक्ष्मण घायल रावण को खत्म करने के लिए तत्पर थे। राम ने उन्हें रोका और कहा कि रावण को सबके सामने युद्ध में पराजित करके मारना जरूरी है, ताकि यह साबित हो जाए कि अधर्म के रास्ते चल कर, फरेब से, छल से चाहे कोई सोने की लंका बना ले, उसका अन्त अशुभ व विध्वंसकारी होता है।

गहलोत जन आक्रोश की आंधी के कारण हार गये, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि जनता गहलोत द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली को जाने व पहचाने जिसने हमारे प्रजातंत्र को इतना विकृत बनाया।

सन् 1989 के लोकसभा चुनाव में गहलोत की जोधपुर से हार, इतिहास में एक मनोरंजक ''फुट नोट'' बनी। पर ग्यारह महीने पहले गहलोत के नेतृत्व में लड़े गये विधानसभा चुनाव में हुई हार ''फुट नोट'' नहीं, बल्कि देश के प्रजातंत्रीय इतिहास में एक ''काले युग'' के अंत के रूप में उल्लिखित रहेगी।

पुरानी लोकोक्ति थी, ''बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है'', पर गहलोत ने तो हर डाल पर चुन-चुन कर हर स्तर पर ''उल्लू'' बिठा दिया, और साथ में ''फ्रीडम'' दे दी कि ''कमाओ और खाओ'' का सिद्धान्त पूर्णतया स्वीकार्य है।

गहलोत के तीसरे कार्यकाल में, भ्रष्टाचार की चरम सीमा की पृष्ठभूमि में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक कार्यरत अफसर ने मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए इन हालात के सन्दर्भ में कहा, ''आप सरकार से गलत समय लड़ लिये, यह लड़ने का नहीं कमाने का समय था। कोई सा भी प्रोजेक्ट ले जाइये मुख्यमंत्री के पास, प्रोजेक्ट पर चिन्तन, उससे लाभ की चर्चा नहीं होती, केवल यह पूछा जाता है, तुम्हें कितना लाभ होगा और उसमें ''हमारी'' क्या हिस्सेदारी होगी।''

तो आज गहलोत के पदच्युत् होने के ग्यारह महीने बाद क्यों गहलोत के व्यक्तित्व पर लिखने की उत्कण्ठा हुई। उत्कण्ठा का कारण था, कि अगर जनता समय से नहीं जागती और गहलोत की शासन प्रणाली को समय की पुकार मानते हुए स्वीकार कर लिया जाता, तो यह स्थापित हो जाता कि जनता तो बेमायने है, हार जीत नारों की विविधता पर निर्भर करती है, नारों के क्रियान्वन पर नहीं।

........इतनी उत्कंठा क्यों?

गहलोत ने अपने कार्यकाल में सरकार और मीडिया के संबंध को भी अपने फायदे अनुसार तोड़ने-मरोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। ज्यादातर स्थानीय मीडिया को विज्ञापनों का प्रलोभन दिया, वहीं अन्य मीडिया को स्पष्ट कह दिया गया कि ''हमारी न्यूज़ छापो, तभी विज्ञापन मिलेंगे।'' विरोधात्मक सोच रखने वाले 42 पत्रकारों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी। जो मीडिया गहलोत से कृतार्थ थी उसने बेधड़क और बिना सूझ-बूझ के वॉट्सएप पर प्रसारित की जा रही फोन-टैपिंग की रिकॉर्डिंग प्रकाशित की, और जाने अनजाने में स्वयं को भी इस राजनैतिक षड्यंत्र का भागीदार बना लिया। क्योंकि गहलोत के मित्र और पार्टी व्हिप महेश जोशी ने इन प्रकाशनों की बिसात पर ही पायलट व उनके गुट के खिलाफ देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी।

मुख्यमंत्री गहलोत में मॉरल (नैतिक) वैल्यू सिस्टम का अभाव, सुप्त अन्तरात्मा, असहाय व मजबूर-सी अफसर शाही, नारे गढ़ने में मास्टरी, आदि, आदि, कारणों ने एक साथ मिलकर पूरे सरकारी ढांचे, प्रशासनिक तंत्र को छकझोर दिया, इतना कि अब उसे पटरी पर आने में कई दशक लगेंगे।

व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा, अपने अशोक जी एक बार फिर एम.पी. का चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी ड्यूटी बनती है, कि तन, मन, धन से पूरा सहयोग करें।

पर उल्लेखनीय बात यह है, कि इस भारी (तन,मन, धन के) समर्थन के बावजूद गहलोत वह चुनाव हार गये थे, जसवन्त सिंह के सामने।

गहलोत यह चुनाव हारेंगे, इसका आभास उस वाकये से हो गया था, जो जोधपुर में लोग–बाग चटकारे ले ले कर आज भी सुनाया करते हैं। वाकये के अनुसार, चुनाव व जन सम्पर्क अभियान के दौरान गहलोत शहर के मोहल्लों व कॉलोनियों में जा रहे थे, जनता के शिकवे, शिकायत सुनने के लिए। एक जगह एकत्रित लोगों ने शिकवे सुनाते हुए कहा, ''सड़क बहुत खराब है, चलना मुश्किल हो रहा है।'' गहलोत ने जवाब में कहा, ''यह स्थानीय प्रशासन का मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।'' लोगों ने बिजली की कम वोल्टेज और बहुत कम समय के लिए बिजली आने का रोना रोया, तो फिर गहलोत ने वो ही जवाब दिया, ''यह तो आर.एस.ई.बी. का काम है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।'' किसी ने लॉ एण्ड ऑर्डर, बढ़ती हुई चोरी–चकारी व गुण्डागर्दी की शिकायत की, पुन: गहलोत की ओर से जवाब मिला, ''यह स्थानीय पुलिस के ''डील'' करने का मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।'' तंग आकर एक आदमी ने हज़ार रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा, ''दिल्ली के चांदनी चौक में बाबा छाप जर्दे का तम्बाकू मिलता है, अगली बार दिल्ली से आयें तो दो डिब्बे लेते आइयेगा।'' व्यंगात्मक टिप्पणी में जनता

पहला मैसेज यह गया कि, दिल्ली इतनी कमज़ोर है कि क्षेत्रीय क्षत्रप, मनमर्जी से बिना लगाम राज चला रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि हाई कमान को भी इस भ्रष्टाचार की कमाई से कोई परहेज नहीं है। परंतु गहलोत को लाभ ही लाभ था इस व्यवस्था से। एक तो उनका भ्रष्टाचार ''जायज़'' हो गया, दूसरा विधायकों की निष्ठा व वफादारी सौ प्रतिशत गहलोत के प्रति हो गई और गहलोत ही क्यों मुख्यमंत्री रहें, इसे ''जस्टिफाई'' करने के लिए (जायज़ ठहराने के लिए) एक और तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनके प्रतिद्वंदी, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ''राजद्रोही'' हैं और उनके खिलाफ ''सैडिशन'' (देशद्रोह) का मुकदमा ठोक दिया गया। ''सैडिशन'' के पक्ष में ''सबूत'' दिये गये कि पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर भाजपा से हाथ मिलाने वाले थे, गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने और कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए।

कहानी पुरानी है तथा इससे सब भली–भांति परिचित हैं, तो आज, गहलोत सरकार गिरने के ग्यारह महीने बाद इस घटनाक्रम की चर्चा क्यों चली है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से प्रजातंत्र बचा हैं।

प्रेस को रौब से दबाने की, या प्यार से सुलाने की नैसर्गिक फितरत होती है हर सरकार की, बहुत कम प्रशासन इस प्रवृत्ति से बच पाते हैं। इस प्रवृत्ति के बारे में स्वर्गीय उपराष्ट्रपति कृष्ण कान्त ने ऐसे ही प्रकरण के बारे में राज्यसभा में बड़े सटीक ढंग से कहा था, ''जब आप खबरों के प्रवाह को जनता तक पहुंचने का मार्ग अवरूद्ध करते हैं, तब आप, अपने तक जानकारियां पहुंचने का रास्ता भी ब्लॉक करते हैं।''

गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री बने, अत: वे अच्छी तरह जानते थे, समझते

गहलोत की राजनीतिक सूझबूझ में कोई कमी नहीं थी, पर इस ज्ञान का वे ''सलैक्टिव'', अपनी सुविधा व व्यक्तिगत हित को देखते हुए प्रयोग करते थे और सुविधानुसार, पार्टी का हित, गौण हो जाता था। जब उन्होंने अपने पुत्र को जालौर से टिकट देने का मन बना लिया, उसे राजनीति में स्थापित करने के लिए तो, कलबियों की संख्या का तर्क गौण हो गया। पर जातियां उनके मन के अनुसार गौण या महत्वपूर्ण नहीं हो जातीं, और उनके पुत्र की डेढ़ लाख वोटों से करारी हार हुई।

पर कैसे रख सकते हैं, जिसे कांग्रेस की राजनीति में माखन लाल फोतेदार का महत्व मालूम नहीं, और जिसने उन्हें यह खबर देने में इतना विलम्ब कर दिया कि वो संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होने से वंचित रह गये।

एक बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत करते हुए बार–बार वे जालौर से किसी ''कलबी'' को टिकट देने पर जोर दे रहे थे। अन्त में मैंने, जो उस समय तक जालौर जिले के जातिगत विश्लेषण से ज्यादा परिचित नहीं था, पूछा कि ''कलबी'' कौन होते हैं और उनको जालौर से टिकट देने पर, इतना जोर क्यों दे रहे हैं वे। उन्होंने समझाया, कलबी, जाटों जैसी मजबूत खेतहर कम्युनिटी है, जालौर में। पर इस कम्युनिटी को अभी तक किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। अत: किसी ''कलबी'' को इस बार यदि कांग्रेस टिकट देती है, तो पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में कई सीटों पर फायदा होगा। उनकी राजनीतिक सूझबूझ में कोई कमी नहीं थी, पर इस ज्ञान का वे ''सलैक्टिव'', अपनी सुविधा व व्यक्तिगत हित को देखते हुए प्रयोग करते थे और सुविधानुसार, पार्टी का हित, गौण हो जाता था। जब उन्होंने अपने पुत्र को जालौर से टिकट देने का मन बना लिया, उसे राजनीति में स्थापित करने के लिए तो, कलबियों की संख्या का तर्क गौण हो गया। पर जातियां उनके मन के अनुसार गौण या महत्वपूर्ण नहीं हो जातीं, और उनके पुत्र की डेढ़ लाख वोटों से करारी

का नारा दिया नेताओं ने, और धीरे–धीरे अफसरों पर हावी हो गये।

तीन बार मुख्यमंत्री रहने के कारण वे सरकारी प्रक्रिया से काफी सुपरिचित हो गये थे। सिस्टम को कैसे और कितना तोड़ा–मरोड़ा जा सकता है, अपने राजनीतिक हित व स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यह खूब समझ गये थे, और किस अफसर को दबाव से, किसको प्रलोभन से, किसको व्यक्तिगत सम्बन्धों से फुसलाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और यह भी कि यदि अफसर फिर भी काबू नहीं आता तो, उसे कहाँ और किस टांड पर रखा जा सकता है, उसके रिटायरमेंट तक। दूसरी ओर दिल्ली पर ''नियंत्रण'' पा लिया, दिल्ली व दिल्ली की ''आवश्यकता'' की पूर्ति करके।

नतीज़ा वो ही हुआ, रेडिएशन से कैंसर के ट्रीटमैंट जैसा। तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत में मॉरल (नैतिक) वैल्यू सिस्टम का अभाव, सुप्त अन्तरात्मा, असहाय व मजबूर–सी अफसर शाही, नारे गढ़ने में मास्टरी, आदि, आदि, कारणों ने एक साथ मिलकर पूरे सरकारी ढांचे, प्रशासनिक तंत्र को छकझोर दिया, इतना कि अब उसे पटरी पर आने में कई दशक लगेंगे। उदाहरण के लिए, ''फोन टैपिंग'' का प्रकरण एक और महत्वपूर्ण मामला है, जिसे बारीकी से देखा जाना चाहिए। पहले तो ऐसा ''फुलप्रूफ'' सिस्टम तैयार किया गया कि कोई सबूत न रहे कि कोई टैपिंग हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, किसी व्यक्ति का फोन ''टैप'' किया जा सकता है, और अगर टैपिंग की अवधि एक सप्ताह से कम है, तो इस टैपिंग की स्वीकृति के लिए कोई फाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। अत: प्रक्रिया यह अपनायी गयी कि पांच–छ: दिनों के लिए फोन ''टैप'' किया गया और फिर एक दो–दिन के लिए फोन को ''टैपिंग' की लिस्ट से निकाल दिया गया, और फिर दो दिन बाद पुन: पांच–छ: दिन की ''टैपिंग लिस्ट'' में डाल दिया गया।

गृह विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस टैपिंग को सात दिन से ज्यादा जारी करने की स्वीकृति नहीं देते, तीन महीने के बाद इस टैपिंग का सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता था।

पर प्रदेश में फोन टैपिंग कांड सिर्फ गैर–कानूनी तरीके से की गई जासूसी का ही एक उदाहरण नहीं है, बल्कि

तीन बार मुख्यमंत्री रहने के कारण वे सरकारी प्रक्रिया से काफी सुपरिचित हो गये थे। सिस्टम को कैसे और कितना तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, अपने राजनीतिक हित व स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस अफसर को दबाव से, किसको प्रलोभन से, किसको व्यक्तिगत सम्बन्धों से फुसलाकर उपयोग में लाया जा सकता है, और यह भी कि यदि अफसर फिर भी काबू नहीं आता तो, उसे कहाँ और किस टांड पर रखा जा सकता है।

ये शिकायतें पहुंचाने का काम विधायक करते हैं। अत: विधायकों को ''खुश'' रखना प्रथम जिम्मेवारी है, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। अत: अपने प्रथम काल में उन्होंने ''डिज़ायर'' कल्चर शुरू किया, किसी भी ''ट्रांसफर, पोस्टिंग'' के चले आ रहे विषय के लिए जिले में विधायक की ''डिज़ायर'' को ही महत्व दिया जायेगा, पार्टी के किसी अन्य नेता को नहीं, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ, व कद में राष्ट्रीय स्तर का माना जाता हो।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, पूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व ए.आई.सी.सी. के महासचिव नवल किशोर शर्मा व नरसिम्हाराव सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी ने इस ''डिज़ायर'' कल्चर के अपने अनुभव शेयर किये। कोटा के भुवनेश चतुर्वेदी, आजीवन अविवाहित रहे पर अपने वृहत् परिवार के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी निभाते रहे। उनका एक भतीजा, जो सरकार की मेडिकल सर्विसेज़ विंग में डॉक्टर था, डेपुटेशन पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में ''पोस्टेड'' था। यह कोई खास बड़ी बात नहीं थी। यह सुविधा, जरा सा भी जो ''कनैक्टेड'' व्यक्ति था उसके रिश्तेदारों को सदा से मिलती आई है। पर अचानक, भुवनेश चतुर्वेदी के भतीजे का एस.एम.एस. से ट्रांसफर हो गया। रामलुभाया उस समय स्वास्थ्य सचिव थे तथा कोटा में कलैक्टर रह चुके थे और भुवनेश चतुर्वेदी के ''महत्व'' से अच्छी तरह परिचित थे। तीन चार बार भुवनेश चतुर्वेदी ने अपने भतीजे के एस.एम.एस. अस्पताल से ट्रांसफर को रद्द करने को कहा, रामलुभाया ने आखिर रद्द कर दिया। तब यह प्रशासनिक प्रथा थी, कि हर महत्वपूर्ण ट्रांसफर, चाहे किसी की भी डिजायर आये, सी.एम.ओ. की स्वीकृति से ही होता था। मुख्यमंत्री ने रामलुभाया को तलब किया और पूछा, ''ये ट्रांसफर रद्द करने के आदेश कैसे निकले, सी.एम.ओ. ने ऐसी कोई ''डिज़ायर'' नहीं भेजी थी।'' सकुचाते हुए रामलुभाया ने जवाब दिया, ''भुवनेश जी कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ व प्रतिष्ठित नेता हैं, उनका कई बार फोन आया, अत:...।'' दो टूक जवाब मिला रामलुभाया को, ''कांग्रेस में कौन वरिष्ठ है और उनकी ''रिक्वैस्ट'' के बारे में क्या निर्णय लेना है, यह सी.एम.ओ. का कार्य क्षेत्र है, आपका नहीं, आगे से ध्यान रखें।''

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज किशोर तिवाड़ी के दामाद का भी कुछ ऐसा ही मामला था। घरेलू परिस्थितियों की वजह से (किसी रिश्तेदार की बीमारी

पहुंचे। मंत्री ने बहुत आवभगत की, सम्मान दिया, ''आप जब नेता थे, तब मैं दरी उठाने वाला साधारण कार्यकर्ता था। आपके आदेश की तुरन्त पालना होगी।'' पर काफी समय बाद भी काम नहीं हुआ तो तिवाड़ी जी ने तहकीकात की, मालूम पड़ा काम तो तभी होगा, जब स्थानीय विधायक अपनी ''डिज़ायर'' स्वीकृति लिख कर भेज देगा।

पण्डित नवल किशोर शर्मा का भी कटु अनुभव कुछ ऐसा ही था। वे विधायक थे, आमेर से, तथा जयपुर के उनके वफादार कार्यकर्ता का विधायकपुरी थाने में कुछ जायज़ काम था। अत: उन्होंने सीधे थानेदार को फोन किया पर काम नहीं हुआ। हर बार कार्यकर्ता नवलजी के पास जाकर पुन: फोन करने का दबाव बनाता रहा। थानेदार का भाई, पी.सी.सी. में विधि सैल का उच्चाधिकारी था, अत: पी.सी.सी. में नवल किशोर शर्मा की वरिष्ठता से खूब परिचित था। पर, थानाधिकारी नवलजी की अवहेलना करता रहा। नवलजी ने अन्त में फोन पर गुस्से में काफी जोरों से डांट–डपट की। एक कार्यकर्ता/नेता ने दबी जुबान में कहा, ''थानेदार तब तक कुछ नहीं करेगा, बाबूजी, जब तक महेश जोशी उसे निर्देश नहीं देता, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर का चार्ज उसे दे रखा है।''

गहलोत जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उनकी इस पकड़ में और ''निखार'' आया और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर तो उन्हें इस धारणा पर स्वयं भी पूर्ण विश्वास हो गया, कि राजस्थान में उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कमान उन्हें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और अधिकांश विधायक अब उनके पार्टनर बन चुके थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर

भागीदारी, ''ऑफिशियल'' हिस्सेदारी देकर, राजनीतिज्ञों, विधायकों की वफादारी खरीद तो ली गहलोत ने, पर विधायक व स्वयं मुख्यमंत्री यह अच्छी तरह जानते थे, अनभिज्ञ नहीं थे, कि इस हिस्सेदारी व भागीदारी की गारंटी तब तक ही है, जब तक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। जब वे पद से हट गये तो, भ्रष्टाचार करने के लिए दिया गया उनका अभयदान बेअसर हो जायेगा। गहलोत ने बखूबी यह समझाया विधायकों को कि, अगर अभयदान बरकरार रखना है और भ्रष्टाचार करने की खुली छूट बरकरार रखनी है, तो गहलोत को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। पर, समझाइश के बावजूद गहलोत व राजनीति की उनकी पद्धति हारी, क्योंकि आम जनता, जिससे भ्रष्टाचार के मार्फत उगाही की जा रही थी, वह भी देख रही थी, ''क्या खेला हो रहा है।'' ममता जी का यह खेला, बंगाल में चल गया, क्योंकि वहां उन्हें 30 प्रतिशत जनता (मुसलमानों) का पूर्ण समर्थन एक मुश्त प्राप्त था, पर यह स्थिति राजस्थान में नहीं थी, किसी जात/जाति का एक मुश्त समर्थन प्राप्त नहीं था गहलोत को।

ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार में भागीदारी का नुस्खा मुख्य रूप से मुसलमानों या उनके कुछ सहयोगियों तक ही सीमित रखना था, पर गहलोत को यह स्कीम पूरे राजस्थान में, सभी चयनित जनप्रतिनिधियों व उनकी दृष्टि में प्रभावशाली वर्गों पर लागू करनी पड़ी, क्योंकि प्रारम्भ से उनका खुद का कोई अपना ''पर्सनल'' वोट बैंक नहीं है और ना ही तीन बार मुख्यमंत्री रहने के बाद बना पाये।

''ट्रांज़ैक्शनरी एप्रोच'' (लेन–देन, खरीद–फरोख्त के व्यवहार) के कारण लोग जुड़े तो सही, आखिर सबका सरकार से कुछ न कुछ काम तो रहता

प्रेस को रौब से दबाने की, या प्यार से सुलाने की नैसर्गिक फितरत होती है हर सरकार की। इस प्रवृत्ति के बारे में स्वर्गीय उपराष्ट्रपति कृष्ण कान्त ने ऐसे ही प्रकरण के बारे में राज्यसभा में बड़े सटीक ढंग से कहा था, ''जब आप खबरों के प्रवाह को जनता तक पहुंचने का मार्ग अवरूद्ध करते हैं, तब आप, अपने तक जानकारियां पहुंचने का रास्ता भी ब्लॉक करते हैं।''

की कुंठा साफ झलक रही थी। गहलोत का वह चुनाव हारना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

सन् 1989 के लोकसभा चुनाव में गहलोत की जोधपुर से हार, इतिहास में एक मनोरंजक ''फुट नोट'' बनी, जिसे पुराने लोग आज भी तत्कालीन युवा गहलोत के राजनीतिक गुरूर व अपरिपक्वता का प्रतीक मानकर, चटकारे लेते हुए याद करते हैं। पर ग्यारह महीने पहले गहलोत के नेतृत्व में लड़े गये विधानसभा चुनाव में हुई हार ''फुट नोट'' नहीं, बल्कि देश के प्रजांतत्रीय इतिहास में एक ''काले युग'' के अंत के रूप में उल्लिखित रहेगी।

यह हार किसी भी तरह एक युवा मंत्री की नादानी, नासमझी, मासूमियत के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। क्योंकि, उस सरकार का नेतृत्व एक ऐसा मुख्यमंत्री कर रहा था, जिसकी, सबसे बड़ी ''क्वालिटी'' (गुण) उसकी राजनीतिक कुटिलता व प्रशासनिक अनुभव थे। जिसका मुख्य ध्येय था, गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखना। जो भी इस ध्येय को प्राप्त करने में मददगार था उसके सौ खून (भ्रष्टाचार के कारनामे) आदि माफ थे, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो। इस नीति को जायज़ ठहराने

थे, जनता अपना मन किस तरह और कैसे बनाती है। इस ''प्रक्रिया'' में क्या–क्या ''फैक्टर्स'' काम करते हैं। उनके पास यह जानकारी भी इकट्ठी हो गई थी कि, राजस्थान में कौन–कौन सी जाति/जात कहां–कहां बसती हैं और जाति/जात का राजनीति की दृष्टि से चुनाव में क्या महत्व है। साथ ही लम्बे काल तक दिल्ली में सक्रिय रहने के कारण, पूर्ण आभास था, कि दिल्ली कैसे निर्णय लेती है, प्रदेशों में पार्टी के नेताओं के बारे में। दिल्ली में किसकी चल रही है, माखनलाल फोतेदार की, सीताराम केसरी की, अहमद पटेल की, गुलाम नबी आजाद की या किसी अन्य की। उन्होंने अपने सेक्रेटरी टु. सी.एम., ललित पंवार को, इस पद से हटा दिया था, क्योंकि देर रात को माखन लाल फोतेदार की मां की मृत्यु हो जाने पर पंवार ने उन्हें तुरंत उठाकर यह जानकारी नहीं दी, और सुबह गहलोत को मृत्यु की खबर बताई। गहलोत ने इस घटनाक्रम से उत्पन्न पीड़ा व व्यथा उस समय मेरे साथ शेयर की, जब वे घर आये थे, और नये सेक्रेटरी टु सी.एम. के चयन के बारे बात कर रहे थे। उन्होंने पंवार को हटाने का निर्णय ले तो लिया था, पर उनकी पीड़ा यह थी कि, उन्होंने एक योग्य व लायक एस.सी.

''ट्रांज़ैक्शनरी एप्रोच'' (लेन-देन, खरीद-फरोख्त के व्यवहार) के कारण लोग जुड़े तो सही, आखिर सबका सरकार से कुछ न कुछ काम तो रहता है। पर, उनके लम्बे राजनीतिक जीवन में, दिल से कोई साथ नहीं जुड़ा। अतः जब तक पद बना रहा, आस-पास मंडराते रहे, पर, मुख्यमंत्री का पद जाते ही भीड़ छंट गई, और राजनीतिक अस्तित्व, रोगी-शैय्या से वक्तव्य देने तक सीमित रह गया।

गहलोत ने किस तरह से फोन टैपिंग का प्रचार-प्रसार करवाया और फिर इस प्रकरण से दूरी बनाए रखने के लिए अपने ही ओ.एस.डी. को निष्कासित किया और पुलिस की जांच झेलने में झोंक दिया।

इस्तीफा देना पड़ा था। परंतु गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में पुलिस और गृह विभाग को जैसे तोड़ा और मरोड़ा उससे ''सत्ता के दुरुपयोग'' की परिभाषा ही बदल जाती है।

सरकारी काम–काज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो शायद शुरू से ही रहा होगा, गहलोत ने इस ''भ्रष्टाचार'' में सबको पार्टनर बना दिया, अफसरशाही, राजनीतिज्ञ आदि। इसकी धुरी बना दिया स्थानीय विधायक को। उदाहरण के लिए, बजरी का अवैध काम, स्थानीय नाके के कर्मचारी, छोटे–मोटे पंच–सरपंच स्तर के नेता, छोटे बीट कॉन्स्टेबल से लेकर उच्चतम स्थानीय नेता (विधायक, मंत्री) शीर्षस्थ स्थानीय पुलिस अधिकारी (थानेदार, डी.वाय.एस.पी., एस.पी.) तथा स्थानीय उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी, सभी की इस ''धंधे'' में हिस्सेदारी तय कर दी गई और धड़ल्ले से ''धंधा'' चला। यह ''इन्स्टिट्यूश्नलाइज़ेशन'' सभी विभागों में प्रचलित हो गया, पर स्थानीय स्तर पर धुरी विधायक/मंत्री को ही रखा गया। क्योंकि, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही, जब पहली बार,

पाठकों को याद दिला दें कि जब फोन टैपिंग के आरोप कर्नाटक सरकार पर लगे थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। परंतु गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में पुलिस और गृह विभाग को जैसे तोड़ा और मरोड़ा उससे ''सत्ता के दुरुपयोग'' की परिभाषा ही बदल जाती है। सरकारी काम-काज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो शायद शुरू से रहा होगा, गहलोत ने इस ''भ्रष्टाचार'' में सबको पार्टनर बना दिया, अफसरशाही, राजनीतिज्ञ आदि। इसकी धुरी बना दिया स्थानीय विधायक को।

के एक कार्यरत अफसर ने मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए इन हालात के सन्दर्भ में कहा, ''आप सरकार से गलत समय लड़ लिये, यह लड़ने का नहीं कमाने का समय था। कोई सा भी प्रोजेक्ट ले जाइये मुख्यमंत्री के पास, प्रोजेक्ट पर चिन्तन, उससे लाभ की चर्चा नहीं होती, केवल यह पूछा जाता है, तुम्हें कितना लाभ होगा और उसमें ''हमारी'' क्या हिस्सेदारी होगी।'' भगवान करे, यह टिप्पणी, केवल मजाक के रुप में कही गयी हो। उसी अफसर ने आगे इसी टोन (लय) में कहा, ऐसा लग रहा है, कि सारे सरकारी तंत्र का एक ध्येय व उद्देश्य था, कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई जाये।

उदाहरण के लिए, जब ''नीट'' का पेपर लीक हुआ और बाज़ार में उपलब्ध होने लगा और पेपर ''लीक'' होने की चर्चा आम होने लगी, तो पहले तो मुख्यमंत्री स्तर पर इन चर्चाओं की, इन खबरों की अनदेखी की गई। शायद आशा थी, ये खबरें अपने आप जनता भूल जायेगी। पर, जब पानी नाक तक आ गया तो एक वक्तव्य आया, कि यह केवल राजस्थान में ही नहीं हो रहा, बल्कि देश के सभी राज्यों में हो रहा है। इस अनदेखी और सतही चेपा–चापी के ''एटिट्यूड'' से पेपर लीक करने का कारोबार धड़ल्ले से चला और नई–नई ''टैक्नीक'' विकसित हुईं। नकली उम्मीदवार बैठने लगे परीक्षा में, सही कागजातों से सुसज्जित हो कर। दायरा भी बढ़ता गया। ''नीट'' का सफल मॉडल, एस.आई. की परीक्षा में लागू कर दिया गया और फिर हर सरकारी परीक्षा में, जो सरकारी नौकरी के लिए ली जाती हैं। नौकरी उन्मुख सरकारी परीक्षाओं में थोड़ी बहुत चीटिंग व सिफारिशें, शायद पहले भी चलती होंगी। पर, गहलोत ने इसे सुसंगठित किया, व्यवस्थित किया और सरकार का प्रश्रय दिया। क्योंकि, मन में यह ''विश्वास'' था, उनसे अधिक योग्य कोई नहीं, और उनका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि उन्होंने सब देवता प्रसन्न कर रखे हैं, चाहे दिल्ली का हाईकमान हो, या राजस्थान के विधायक, चाहे विपक्ष के नेता और बड़े से बड़े अफसर।

''करप्शन'' (भ्रष्टाचार) में

है। पर, उनके लम्बे राजनीतिक जीवन में, दिल से कोई साथ नहीं जुड़ा। अत: जब तक पद बना रहा, आस–पास मंडराते रहे, पर, मुख्यमंत्री का पद जाते ही भीड़ छंट गई, और राजनीतिक अस्तित्व, रोगी–शैय्या से वक्तव्य देने तक सीमित रह गया।

तो आज गहलोत के पदच्युत होने

''नीट'' का पेपर लीक हुआ और बाज़ार में उपलब्ध होने लगा और पेपर ''लीक'' होने की चर्चा आम होने लगी, तो पहले तो मुख्यमंत्री स्तर पर इन चर्चाओं की, इन खबरों की अनदेखी की गई। जब पानी नाक तक आ गया तो एक वक्तव्य आया, कि यह केवल राजस्थान में ही नहीं हो रहा, बल्कि देश के सभी राज्यों में हो रहा है। इस अनदेखी और सतही चेपा-चापी के ''एटिट्यूड'' से पेपर लीक करने का कारोबार धड़ल्ले से चला और नई-नई ''टैक्नीक'' विकसित हुईं। नकली उम्मीदवार बैठने लगे परीक्षा में।

के ग्यारह महीने बाद क्यों गहलोत के व्यक्तित्व पर लिखने की उत्कण्ठा हुई। उत्कण्ठा का कारण था, कि अगर जनता समय से नहीं जागती और गहलोत की शासन प्रणाली को समय की पुकार मानते हुए स्वीकार कर लिया जाता, तो यह स्थापित हो जाता कि जनता तो बेमायने है, हार जीत नारों की विविधता पर निर्भर करती है, नारों के क्रियान्वन पर नहीं।

प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, किसी व्यक्ति का फोन ''टैप'' किया जा सकता है, और अगर टैपिंग की अवधि एक सप्ताह से कम है, तो इस टैपिंग की स्वीकृति के लिए कोई फाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। अतः प्रक्रिया यह अपनायी गयी कि पांच-छः दिनों के लिए फोन ''टैप'' किया गया और फिर एक दो-दिन के लिए फोन को ''टैपिंग' की लिस्ट से निकाल दिया गया, और फिर दो दिन बाद पुनः पांच-छः दिन की ''टैपिंग लिस्ट'' में डाल दिया गया। गृह विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस टैपिंग को सात दिन से ज्यादा जारी करने की स्वीकृति नहीं देते, इसलिए तीन महीने के बाद इस टैपिंग का सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता था।

के लिए तर्क दिया गया कि, पैसे दिल्ली पहुंचाने पड़ते हैं, तो ''कलैक्शन'' तो करना ही पड़ेगा। आश्चर्य तो यह है कि दिल्ली ने इस स्थिति को कैसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि, इस रणनीति से हाईकमान को नुकसान ही नुकसान था।

अफसर को इतने महत्वपूर्ण पद से हटा तो दिया था, और उन्हें इसका भारी राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

पर, उन्हीं के शब्दों में, वे राजनीतिक दृष्टि से ऐसे ''अपरिपक्व'' अफसर को संवेदनशील पद (सेक्रेटरी टु सी.एम.)

हार हुई, जालौर की सीट पर। कलबी ''कम्युनिटी'' को काफी सख्त नाराज़गी थी, ''कलबी'', जो कांग्रेस के परम्परागत वफादार समर्थक रहे हैं, को ''कलबी'' बाहुल्य सीट से, ''कलबी'' का टिकट काट कर, एक बाहरी को, अपने पुत्र को, टिकट देने से।

मेदांता हॉस्पिटल में हुए मेरे छोटे भाई के कैंसर के ''ट्रीटमैंट'' के दौरान एक बात समझ आई। बत्तीस राउण्ड हुए थे रेडिएशन के। एक रेडिएशन के राउण्ड में तीन अलग–अलग पावरफुल रेडिएशन की किरणें, कैंसर ग्रसित गांठ पर एक साथ पहुंचती थीं, तथा ये तीन किरणें एक साथ मिल कर इतनी पावरफुल बन जाती थीं कि कैंसर की गांठ बत्तीस राउण्ड के बाद ''डिज़ॉल्व'' हो गई थी। राजस्थान में सरकारी कामकाज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तथा जातिवाद/जातवाद सम्भवतया शुरू से ही रहा है। पर, कुछ परम्पराओं का दबाव, लोक लाज की शर्म, अन्तरात्मा की आवाज़, सरकारी कामकाज की प्रक्रिया से पूर्ण परिचय ना होना, कुछ अफसरों की पढ़ाई व एक्सपोज़र राजनीतिज्ञों से ज्यादा व बेहतर होना, ने एक अंकुश का काम किया। राजनीतिज्ञों और नेताओं को मनमानी करने से रोका। प्रारंभिक दिनों में अधिकतर सरकारी अफसर राजस्थान के रहने वाले नहीं थे, अत: स्थानीय परिस्थितियों से ज्यादा परिचित होने का, जनता की नब्ज़ समझने

राजनैतिक लाभ के लिए कुटिलता से रचित एक ऐसा प्रकरण है जिससे अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों की विश्वसनीयता को धूमिल करने का एक षड्यंत्र किया गया। गहलोत सरकार के इशारों पर, पायलट और पायलट गुट की छवि धूमिल करने के लिए दो नेताओं की फोन टैपिंग का कुछ अंश पहले ''वॉट्सएप'' पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हैरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की ''जैन्विननैस'' व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के पश्चात् जब यह शोर गुल बिल्कुल ही ठंडा हो गया कि ''पायलट भाजपा में जा रहे हैं'', तब मान–हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का व्यक्तित्व इस बात से उजागर होता है कि एक तरफ उन्होंने फोन टैपिंग का प्रचार–प्रसार करवाया और फिर इस प्रकरण से दूरी बनाए रखने के लिए अपने ही ओ.एस.डी. को निष्कासित किया और पुलिस की जांच झेलने में झोंक दिया।

पाठकों को याद दिला दें कि जब फोन टैपिंग के आरोप कर्नाटक सरकार पर लगे थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री पद से

प्रथम कार्यकाल में उन्होंने ''डिज़ायर'' कल्चर शुरू किया, कि, किसी भी ''ट्रांसफर, पोस्टिंग'' के चले आ रहे विषय के लिए जिले में विधायक की ''डिज़ायर'' को ही महत्व दिया जायेगा, पार्टी के किसी अन्य नेता को नहीं, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ, व कद में राष्ट्रीय स्तर का माना जाता हो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, पूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व ए.आई.सी.सी. के महासचिव नवल किशोर शर्मा व नरसिम्हाराव सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी ने इस ''डिज़ायर'' कल्चर के अपने अनुभव शेयर किये।

''इमरजैन्सी'' के बाद वे जोधपुर से एम.पी. बने थे, तथा प्राय: दिल्ली ही रहने लगे थे, तब गहलोत ने निष्कर्ष निकाल लिया था, कि कांग्रेस के किसी राजनीतिज्ञ को सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कि दिल्ली के पास, उस मुख्यमंत्री की शिकायतें नहीं पहुंचें और

के कारण) दामाद की जयपुर पोस्टिंग चाहते थे। तत्कालीन स्वास्थ्यमंत्री, तिवाड़ी जी से काफी जूनियर थे पार्टी में, अत: तिवाड़ी जी ने पोस्टिंग के लिए बातचीत की तो मालूम पड़ा स्वास्थ्य मंत्री से मिलना होगा। वो बेहिचक मंत्री महोदय से मिलने, मंत्री जी के दफ्तर

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

कोटा

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

कोटा, शनिवार 26 अक्टूबर, 2024

KEDIA सेजस्थान

महा दिवाली

15 लाख

15 लाख

15 लाख

FIXED PRICE GUARANTEED

NO MIDDLE-MEN

दिवाली पर 15 लाख रेट बढ़ेगी !

दिवाली बाद करोड़ों में मिलेगी कोठी !

SPORTS AMENITIES

- BASKET BALL COURT
- BADMINTON COURT
- SKATING RINK
- LAWN TENNIS COURT
- MINI GOLF
- CRICKET PRACTICE NET
- BOX CRICKET
- JOGGING LOOP
- CYCLING TRACK

OUTDOOR AMENITIES

- RASHI GARDEN
- OPEN AIR THEATRE
- WETLAND PARK
- KID'S PLAY AREA
- SANDPIT
- OPEN GYM
- LAP POOL
- KID'S POOL
- ROOF TOP WALK
- MULTI PURPOSE LAWN
- MEDITATION ZONE
- VOCATIONAL WORKSHOP SPACE
- SENSORY WALK
- NATURE TRAIL
- SAVANNA ELEVATED TRAIL
- PICNIC POINTS
- ADVENTURE PLAY AREA

INDOOR AMENITIES

- TUITION ROOM
- LIBRARY
- ART AREA
- KID'S WORKSHOP AND PLAY AREA
- DISNEY THEME GAME ROOM
- CONFERENCE ROOM
- GYMNASIUM
- YOGA AREA
- CARD AREA
- CHESS AREA
- CARROM AREA
- TABLE TENNIS
- BILLIARDS

वॉक-अप अपार्टमेंट्स

63.45 लाख से शुरु

कोठी

84.60 लाख से शुरु

गिनती की कुछ ही कोठी बची हैं।

KEDIA सेजस्थान

KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड़, जयपुर

POSSESSION: DEC. 2025

बड़ी-बड़ी कोठी, बड़े-बड़े फ्लैट

KEDIA®

1800-120-2323

78770-72737

info@kedia.com

www.kedia.com

www.rera.rajasthan.gov.in

RERA No. RAJ/P/2023/2387

SCAN QR FOR

- LOCATION
- ROUTE MAP
- SITE 360 TOUR
- E-BROCHURE
- WALKTHROUGH

*T&C Apply

विचार बिन्दु

शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं, किन्तु जो उसके अनुसार आचरण करता है वो ही वस्तुतः विद्वान है। –अज्ञात

त्योहारी सीज़न में ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें

हमारे देश में घर-घर में डिजिटल क्रांति प्रवेश कर चुकी है। अब हमारे खरीद फरोख्त के लगभग सभी काम डिजिटली होने लगे हैं। बच्चे से बुजुर्ग तक के हाथों में स्मार्ट फोन आने से अब शायद ही कुछ ऐसी चीज बची हो जिसके लिए आप डिजिटल पेमेंट ना करते हो। लोग कैश रखने के बजाय डिजिटली पेमेंट देना ज्यादा पसंद करते हैं। इस समय देश में त्योहारी सीज़न चल रहा है जो नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक चलेगा। इस दौरान लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे दर्जनों प्लेटफॉर्म पर जोरदार सेल का धमाका देखने को मिल रहा है। लोग धड़ाधड़ खरीदारी में जुटे है। प्रतिदिन लाखों-करोड़ों रुपयों की खरीदारी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही त्योहारी सीजन में खरीदारी के दौरान डिजिटल पेमेंट फ्रॉड का जोखिम भी बढ़ गया है। लोग आकर्षक लुभाने वाले ऑफर्स और डिस्काउंट्स के चलते लोग भारी खरीदारी त्योहारी सीजन में करते हैं। एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कई बार उपभोक्ता प्लेटफॉर्म की वैधता की जांच को नजरअंदाज कर देते हैं। फ्रॉड होने का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। डिजिटल पेमेंट्स के जरिए लोगों को धोखा देकर फंसाना भी आसान हो गया है। धोखाधड़ी के तरीके भी अब काफी आसान हो गए हैं। इस बीच साइबर जालसाज भी काफी सक्रिय हो गए हैं और साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उपभोक्ताओं को ऑफलाइन खरीदारी की अपेक्षा ऑनलाइन खरीदारी करना अधिक पसंद आता है। ऑनलाइन खरीदारी करना फायदेमंद होता है जहां अपनी पसंद की और कम कीमत पर कई वैराइटी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कई बार ऑनलाइन खरीदारी करना भारी भी पड़ जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल शुरू होते ही जालसाज भी सक्रीय हो जाते हैं। जो आपकी एक गलती पर आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। मीडिया में ऐसी घटनाओं के समाचार रोज ही पढ़ने को मिल रहे है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट के दौरान हर स्तर पर सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके। डिजिटल पेमेंट करें तो आप खास तौर पर ध्यान रखें, जिनसे आपको फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। आप किसी लिंक के जरिए या किसी ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट कर रहे हों तो यह ध्यान रखे यह पेमेंट सुरक्षित है या नहीं। उस कंपनी के बारे में ऑनलाइन रिव्यू चेक करें। उस वेबसाइट के बारे में पता करें। इस सीजन में खरीदारी के दौरान सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। कहते है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।

भारत में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसके बाद लगातार देश इस क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाये हुए है। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर वनबन गया है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। तेजी से बढ़ता डिजिटल लेनदेन बढ़ती हुई खपत को दर्शाता है। यह डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। आरबीआई के डाटा के अनुसार देश भर में पेमेंट परफॉर्मेंस और पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचे में वृद्धि की वजह से डिजिटल पेमेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि सभी मापदंडों में हुई है। डाटा के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक देश भर में डिजिटल पेमेंट में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2024 के अंत में 445.5 पर था, जबकि सितंबर 2023 में 418.77 और मार्च 2023 में 395.57 था। भारत में मोबाइल पेमेंट स्मार्टफोन के आने और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के बाद बहुत आसान हो गया। विशेषकर युवाओं में मोबाइल से भुगतान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ग्लोबल डेटा के मुताबिक 2028 तक भारत में मोबाइल वॉलेट के माध्यम से भुगतान 531.8 ट्रिलियन रुपये के आंकड़े को पार करने का अनुमान है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट के दौरान हर स्तर पर सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके। डिजिटल पेमेंट करें तो आप खास तौर पर ध्यान रखें, जिनसे आपको फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। आप किसी लिंक के जरिए या किसी ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट कर रहे हों तो यह ध्यान रखे यह पेमेंट सुरक्षित है या नहीं।

एक अधिकृत जानकारी के अनुसार देश भर में पेमेंट परफॉर्मेंस और पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचे में वृद्धि की वजह से डिजिटल पेमेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि सभी मापदंडों में हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले पांच महीनों में डिजिटल पेमेंट का मूल्य बढ़कर 1,669 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि के दौरान डिजिटल पेमेंट का लेन-देन 8,659 करोड़ तक पहुंच गया। यूपीआई लेन-देन का मूल्य 138 प्रतिशत की सीएजीआर पर 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 200 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा पिछले 5 महीनों में कुल लेन-देन का मूल्य बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यूपीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी है जहां वित्त वर्ष 2017-18 में यूपीआई लेनदेन 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 129 प्रतिशत की सीएजीआर से 13,116 करोड़ हो गया है। जैसे तेज पेमेंट सिस्टम को अपनाने में तेजी लाने के प्रयासों ने वित्तीय लेन-देन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे लाखों लोगों के लिए रीयल-टाइम, सुरक्षित और सीमलेस पेमेंट संभव हुआ है। मार्केट रिसर्च फर्म डेटाम इंटेलिजेंस की रिर्पोट के अनुसार इस साल त्योहारी सीजन में ऑनलाइन बिक्री 12 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 9.7 बिलियन डॉलर से 23 प्रतिशत अधिक है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में तीस करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन भुगतान करते है। दुकानदार और ऑनलाइन कम्पनियाँ जहां इन त्योहारों में आकर्षक ऑफर तथा डिस्काउंट की पेशकश कर ग्राहकों को रिझाने का प्रयास करते हैं, वहीं ग्राहक भी इन आकर्षक ऑफरों का लाभ उठाकर जमकर खरीदारी करते हैं। सरकारी बैंकों सहित कई कम्पनियाँ और निर्माता उपभोक्ताओं को लुभावनी छूट से भी लाभान्वित कर रहे है। खुदरा व्यापारी ऑनलाइन सेल का विरोध कर रहे है और अपने व्यापार के चौपट होने की दुहाई दे रहे है मगर उपभोक्ता ऑनलाइन व्यापार से खुश नजर आ रहे है। उन्हें बाजार की धकमपेल से छुटकारा मिल रहा है। ऑनलाइन सेल में सामान सस्ता जरूर मिल रहा है मगर उपभोक्ता को सावधानी रखनी पड़ेगी क्योकि ठगी करने वाले गिरोह भी सक्रीय हो गए है। जो भोले भले लोगों को सस्ते माल के चक्कर में फंसा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे है। ऐसे में लोगों ने सतर्कता नहीं रखी तो सस्ते में माल खरीदना महंगा भी पड़ सकता है।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राशिफल शनिवार 26 अक्टूबर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2081, आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 9:46 तक, शुक्ल योग रविवार प्रातः 5:57 तक, वणिज करण सायं 4:23 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 9:46 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-तुला, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मिथुन, बुध-तुला, गुरू-वृष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज ज्वालामुखी योग प्रातः 9:46 तक है। भद्रा सायं 4:23 से आरम्भ होगी। महापात योग रात्रि 2:10 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ 8:00 से 9:24 तक, चर 12:11 से 1:34 तक, लाभ-अमृत 1:34 से 4:21 तक।

राहूकालः 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 4:37, सूर्यास्त 5:45

मेष

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह

नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृष

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

कन्या

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय बना रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मकर

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मिथुन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

तुला

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा।

कुंभ

घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

मीन

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

प्रजातंत्र में संसद, सड़क और संस्कृति

प्रो. कैलाश सोडाणी

सैकड़ों वर्षों की गुलामी और गरीबी से मुक्ति के लिए लगभग 200 वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 1947 में जाकर आजाद भारत का स्वप्न साकार हुआ। आजाद भारत किस मार्ग पर चलेगा इसके लिए प्रजातंत्र के तत्कालीन आदरणीय पुरोधाओं ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। उसी संविधान के तहत। देश को देश के मतदाताओं से सृजित संसद जैसा एक शानदार तौहफा प्राप्त हुआ।

संसद कोई इमारत नहीं है अपितु भारत के मतदाताओं की भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने भारतीय प्रजातंत्र को दुनियाँ की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में श्रेष्ठ पायदान पर पहुँचाया है। संसद पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अपना मत एवं विचार प्रकट करने के लिए श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च प्लेटफार्म है। हमारी संसद में अनेक बार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, परिचर्चा एवं बहस बड़ी विद्वत्तापूर्ण एवं रोचक रही है। संसद की बहस को गरिमा प्रदान करने वालों में प्रमुख है - वी.के. कृष्णामेनन, पीलू मोदी, फिरोज गाँधी, राममनोहर लोहिया, मधु लिमये, सोमनाथ चटर्जी, अटल बिहार वाजपेयी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, सुधांशु त्रिवेदी। साथ ही सांसदों द्वारा आये दिन होने वाली नारेबाजी एवं बहिष्कार से संसद का बहुमूल्य समय बहुत खराब होता है। इस प्रकार का शोर-शराबा संसद की गरिमा एवं हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है।

संसद की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेदारी पक्ष एवं विपक्ष दोनों की है, इसके लिए सभी सांसदों से मर्यादित एवं अनुशासित आचरण अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में लोकसभा अध्यक्ष से भी यह अपेक्षा रहती है कि वे विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान करें। सौभाग्य से यह काम हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष बखूबी निभा रहे हैं। एतदर्थ विपक्षी सांसद उनके प्रति विश्वास एवं श्रद्धा का भाव रखते हैं।

अब मैं आलेख के मूल विषय पर आता हूँ कि प्रजातंत्र में संसद के साथ-साथ सड़क की राजनीति का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान एवं वजूद है। जब विपक्ष को यह लगता है कि संसद के माध्यम से वह अपनी बात कह नहीं पा रहा है तो फिर विपक्ष धरना, प्रदर्शन, बन्द इत्यादि के माध्यम से सड़क की राजनीति प्रारम्भ करता है, जिसे हमारे देश में पर्याप्त प्रेस कवरेज़ भी मिल जाता है। अंततः विपक्ष अपनी बात मतदाताओं तक पँहुचाने में सफल भी होता है। 1972-74 में जयप्रकाश नारायण का जन आन्दोलन, 1990-91 में श्री राम जन्मभूमि के लिए लालकृष्ण आडवाणी की रथ-यात्रा, 2013-14 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन, 2023-24 में राहुल गाँधी की भारत जोड़ो यात्रा आदि कुछ ऐसे उदाहरण है जो यह दर्शाते हैं कि संसद के बाहर भी अपनी बात को बहुत बेबाक तरीके से समाज के समक्ष रखा जा सकता है।

संसद और सड़क की राजनीति की श्रेष्ठता के लिए हमें हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति को हमेशा याद रखना होगा। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप ही संसद एवं सड़क पर अनुशासित संवाद एवं आचरण होना चाहिये। निःसन्देह प्रजातंत्र को जीवन्त बनाये रखने के लिए धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन सभी आवश्यक है परंतु आन्दोलन में भी हमें हमारी संस्कृति एवं मूल्यों को नहीं भूलना चाहिये। आन्दोलन का मतलब अनुशासनहीनता नहीं है। जैसे किसान आन्दोलन के समय राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करना, राजस्थान में आरक्षण को लेकर रेलों के आवागमन को बाधित करना, दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क पर किये धरना-प्रदर्शन से महीनों तक दिल्लीवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। आन्दोलन के नाम पर आगजनी, तोड़फोड़, बाजार बन्द, चक्का जाम आदि शुद्ध अनुशासनहीनता है। यह प्रजातंत्र के दुरुपयोग के साथ-साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की अवहलेना भी है। व्यक्ति या समूह सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए आन्दोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु आम नागरिकों को उनके आन्दोलन से कोई असुविधा एवं कष्ट नहीं होना चाहिये। किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान न तो किसी नागरिक को होना चाहिये और न ही सरकार को। यह देखना भी आंदोलनकारियों का कर्तव्य है। भारतीय प्रजातंत्र की मजबूती एवं प्रखरता के लिए संसद और सड़क दोनों जगह भारतीय संस्कृति के अनुरूप मर्यादित एवं अनुशासित आचरण रखना होगा।

–प्रो. कैलाश सोडाणी,
कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रयाग महाकुंभ-2025 : सांस्कृतिक महत्व

राजेन्द्र जोशी

अमृत कहां बरसेगा। यह पहले से तय है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में अधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है- कलश, ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिह्न है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। इस बार त्रिवेणी संगम प्रयाग में 45 दिन का अमृत काल होगा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में भी पाया जाता है। इस प्रकार, कुम्भ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला है।

इन दिनो महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन हेतु इंडिया थिंक काउंसिल भारत के विभिन्न स्थानों पर कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। कुंभ कान्क्लेव का आयोजन छोटी काशी में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 3 अक्टूबर 2024 को किया गया। इस कॉन्क्लेव में महाकुंभ मेले के संदर्भ में सार्थक चर्चा हुई। कुंभ मेले के सांस्कृतिक संदर्भ विषय पर इस तरह की यह पहल सराहनीय है। ऐसी चर्चा के आयोजन के लिए इंडिया थिंक एवं प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी का आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में एक सार्थक चर्चा का आयोजन किया।

वैसे भी बीकानेर और संगम का एक महत्वपूर्ण रिश्ता जुड़ता है, प्रयाग में तीन नदियों का संगम है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इतिहास यह कहता है कि थार के मरुस्थल बीकानेर में कभी सरस्वती नदी का प्रवाह हुआ करता था। हम अभी सरस्वती नदी की गोद में रह रहे हैं। इसका मतलब हम भी कल्पवास का हिस्सा है। महाकुंभ मेला भव्य- दिव्य और नव्य थीम पर आयोजित हो रहा है। 400 मिलियन लोगों की संभावना 40 करोड लोग इस महाकुंभ में शामिल होंगे।

संगम की पवित्र धरती प्रयाग का महाकुंभ 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से लेकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक संचालित होगा। कुल 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में देश-विदेश से हजारों-हजार श्रंदालु प्रयागराज पहुँच रहे है। महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं, 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को पॉलीथीन फ्री और ठीन कुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए जहां महाकुंभ में पॉलिथीन को प्रतिबंधित किए जाने की तैयारी है. वहीं तीन लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं।

इन पौधों को सरकार संरक्षित भी करेगी। महाकुंभ के आयोजन हेतु 5154 करोड़ की 327 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।इसके साथ ही 1264 करोड़ की 75 विभागीय परियोजनाओं पर भी काम प्रारंभ हो चुका है। महाकुंभ से जुड़ी सभी स्थाई और अस्थाई परियोजनाओं को अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए अनुभवी अधिकारियों की टीम दिन-रात काम में जुटी है।

इन प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम :- 2019 में आयोजित दिव्य और भव्य कुंभ से भी 2025 को बेहतर आयोजित करने की तैयारी चल रही है। महाकुंभ के बेहतर आयोजन के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा इसका क्षेत्रफल जहां बढ़ाया जा रहा है, वहीं मेले में अतिरिक्त सुविधाएं भी मुहैया कराए जाने की तैयारी है। मेले का क्षेत्रफल बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है. कुल 25 सेक्टर में मेला बसाया जाएगा, जबकि 1900 हेक्टेयर में छह पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। महाकुंभ मेले में 25000 लोगों के लिए पब्लिक अकोमोडेशन, मोटरबोट, चेंजिंग रूम, पूजा स्थल और फ्लोटिंग जेटी बनाई जाएगी। मेले में इस बार 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र भी बनेंगे, पहली बार यमुना नदी के वीआईपी घाट पर पक्के घाट का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर भी पक्का घाट बन रहा है। यातायात की समस्या को देखते हुए तेलियरगंज से संगम क्षेत्र तक 13 किलोमीटर का रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। वर्ष भर घाटों पर जल का प्रवाह बना रहे इसके लिए ड्रेजिंग भी कराई गई। महाकुंभ से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में सड़कों और चौराहों का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट विस्तार के साथ ही अनेक फ्लाई ओवर बनाए जा रहे है।

महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अक्षय वट, पाताल पुरी, सरस्वती कूप, हनुमान मंदिर, श्रृंगवेरपुर धाम और भारद्वाज कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जा रहा है। अक्टूबर - दिसंबर 2024 तक मेले में सभी संस्थाओं को जमीन और सुविधाओं का आवंटन कर दिया जाएगा। इस बार खास तौर पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए जमीनों और सुविधाओं के आवंटन की तैयारी की गई है।

श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाः -श्रद्धालु और पर्यटक सुगमता से महाकुंभ मेले में आकर सुरक्षित वापस जा सके इसके लिए तैयारी की जा रही हैं। एयरपोर्ट पर जहां एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, वहीं एयरपोर्ट से लेकर महाकुंभ मेले तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही सड़क को विश्व स्तरीय स्मार्ट रोड बनाया जा रहा है। इस सड़क के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट और कुंभ कलश बनाए जाएंगे। इसके अलावा सड़क किनारे आकर्षक पेंटिंग की जाएगी ताकि एयरपोर्ट से महाकुंभ मेले के अंदर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुखद अनुभूति का एहसास कराया जा सके। प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले नौ रेलवे स्टेशनों पर भी बुनियादी सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग

महाकुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे से लेकर ड्रोन कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में इस बार भी तीन शाही स्नान होंगे। पहला स्नान पर्व 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का होगा। जबकि 14/15 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान होगा। 29 जनवरी मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान एवं 3 फरवरी बसंत पंचमी को तीसरा और आखिरी शाही स्नान प्रयागराज में होगा। जिसके बाद 5 फरवरी को अचला सप्तमी का स्नान पर्व होगा। जबकि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ कल्पवास का समापन होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा।

प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) जिले में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर अस्थायी तम्बू शहर के प्रस्तावित 25 सेक्टरों में सड़क परियोजनाओं, अस्थायी पुलों, अस्पतालों, बाजारों आदि की एक श्रृंखला विकसित की जाएगी। श्रद्धालु हिंदू प्रयागराज को सबसे पवित्र शहरों में से एक मानते हैं, जहां संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

संभवतः, दुनिया का सबसे बड़ा 4,000 हेक्टेयर का टेंट सिटी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अनुमानित 400 मिलियन तीर्थयात्रियों की मेजबानी की जाएगी।

जनवरी-फरवरी 2025 में महाकुंभ के पावन 45 दिनों के दौरान 400 मिलियन लोगों का एकत्रीकरण, जो अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त जनसंख्या के बराबर होगा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या, जो 250 मिलियन है, का 1.6 गुना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, 67,000 स्ट्रीट लाइटों से जगमगाने वाले इस टेंट शहर में पर्यटकों की सेवा के लिए 2,000 टेंट और 25,000 सार्वजनिक आवास होंगे

स्वच्छता का माडल होगा महाकुंभ

स्वच्छता के माडल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 1.45 लाख शौचालय बनाए जाएंगे।

भव्य-दिव्य और नव्य थीम

पिछले कुंभ 2019 का थीम दिव्य व भव्य कुंभ था। इस बार 2025 के महाकुंभ में एक शब्द और जोड़ दिया गया है। भव्य-दिव्य और नव्य महाकुंभ इस बार का थीम होगा। सरकार की ओर से इस पर स्वीकृति भी दे दी गई है।

सरकार महाकुंभ-2025 को भव्य, दिव्य और नव्य स्वरूप दे रही है। कुंभ नगर को जिले का दर्जा मिलेगा और यहां जिला स्तरीय अधिकारी तैनात होंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कुंभ क्षेत्र का विस्तार किया गया है। महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने के अनुमान के मुताबिक ही बसावट में बदलाव किया गया है।

कुंभ मेला क्षेत्र का विस्तार 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में होगा। पिछला कुंभ 3200 हेक्टेयर में बसा था। इस बार 25 सेक्टर में महाकुंभ बसाया जाएगा। सेक्टर का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के लिए गंगा पर 30 पांटून पुल बनेंगे। पिछली बार 22 पांटून पुल बने थे, जबकि इस बार 30 पांटून पुलों का निर्माण होगा।

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद्-साहित्यकार

खाटूश्यामजी में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण, 360 किलो दूषित मिठाई नष्ट कराई

बेसन के लड्डू, बेसन की चक्की दूषित मिली, सोयाबिन तेल खराब मिला

खाटूश्यामजी/सीकर, (निसं)। दीपावली त्योहार पर आमजन को शुद्ध व ताजा खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा व सीएमएचओ डॉ. निर्मल सिंह के निर्देशन में शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की ओर से खाटूश्यामजी में कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि खाटूश्यामजी में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुये 360 किलो दूषित मिठाई की नष्ट की साथ ही बूंदी के लड्डू व सोयाबीन के नमूने लिए।

एफएसओ मदनलाल बाजिया, महमूद अली व नंदराम मीणा ने अंतिमा स्वीट स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान 250 किलो बेसन के लड्डू, 110 किलो बेसन की चक्की दूषित पाई गई तथा 25 लीटर सोयाबिन तेल खराब पाया गया, जिनको मौके पर ही नष्ट करवाया गया तथा बेसन बूंदी के लड्डू, वनस्पती घी के नमूने लिए गए। इस दौरान श्याम प्रेमी शुद्ध मिष्ठान भंडार के यहां से केशर मावा पेड़ा, शेखावत मिष्ठान भंडार के यहां से मावा पेड़ा, श्री श्याम फूड प्लाजा के यहां बेसन बूंदी लड्डू के सैम्पल लिए गए। सभी सैम्पलों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया। खाद्य कारोबारियों को दीपावली पर्व पर आवश्यकता से अधिक मिठाई नहीं बनाने तथा फूड कलर का उपयोग एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों के अनुसार ही करने के लिए पाबंद किया गया। टीम में अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी नन्दराम मीणा, श्रवण कुमार, दिनेश कुमार, राजेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, कुलदीप सिंह, सुमेर सिंह व अरविंद फोगाट शामिल रहे।

■ दूषित मीठाइयों को मौके पर नष्ट कराया, ''शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान'' के तहत कार्रवाई की

रामगढ़ शेखावाटी तहसील में 26 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये : जिला रसद अधिकारी सीकर नरेश शर्मा ने बताया कि जिले में अवैध एलपीजी रिफिलिंग एवं दुरूपयोग को रोकने के लिए शुक्रवार को जिला रसद विभाग की 6 प्रवर्तन निरीक्षकों की टीम ने रामगढ़ शेखावाटी तहसील में कार्रवाई के दौरान 26 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गए जो घरेलू गैस सिलेण्डरों का होटल, मिठाई बनाने आदि में व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि रसद विभाग की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए युवा आगे आएं : राज्यपाल बागड़े

अचरोल, (निसं)। अपेक्स यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन अचरोल कैंपस में हुआ, जहां प्रशासनिक भवन से दीक्षांत परेड प्रारंभ होकर दीक्षांत स्थल तक पहुंची। समारोह का प्रारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, अध्यक्षता कर रहे युनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉ. रवि जूनीवाल और विशिष्ट अतिथि आचार्य बालकृष्ण, कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं निहालचंदए भूतपूर्व सांसद लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर ने बेस्ट स्टूडेंटस को डॉ. सागरमल जूनिवाल मेमोरियल अवार्ड सहित विभिन्न संकायों में 15 टॉपर्स को गोल्ड मैडल प्रदान किए गए। आयुर्वेद, योग के क्षेत्र में नए अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के लिए अपने असाधारण और अविस्मरणीय योगदान के लिए आचार्य बालकृष्ण एवं सबसे कम उम्र में लोकसभा सांसद बने और पाँच बार सांसद रह चुके भूतपूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री निहालचंद को समाज के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डीण् लिटण् की मानद उपाधि प्रदान की गई।

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। विद्या वही है जो जीवन की समस्याओं का सटीक हल खोजने में सहायता करे। मुझे प्रसन्नता है कि अपेक्स विश्वविद्यालय इसी दिशा में काम कर रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को आगे लाकर शिक्षा देने का आपका प्रयास सराहनीय है। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत ने विश्व को बहुत से नवाचार और आविष्कार दिए हैं। आप इस महान परम्परा को आगे बढ़ाएं। ज्ञान का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान आपको आगे बढाता है, आप देश को आगे ले जाएं। मैं आपको विभिन्न स्तरों पर उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत.बहुत बधाई देता हूं।

विशिष्ट अतिथि आचार्य बालकृष्ण ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। युनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉ रवि जूनीवाल ने अपने दीक्षांत भाषण में डिग्री पाने वाले सभी प्रतिभाओं को बधाई दी। इस दीक्षांत समारोह में यूजीए पीजी एवं रिसर्च स्टूडेंट्स को डिग्रियां वितरित की गई।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 14 प्रभात कोटा, शनिवार 26 अक्टूबर, 2024 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा के चुनाव नतीजों का असर नहीं होगा

क्योंकि हरियाणा में भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से था, पर, महाराष्ट्र में कांग्रेस, गठबंधन की जूनियर पार्टनर मात्र है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। दो सौ अठयासी सीटों वाले महाराष्ट्र तथा 81 सीटों वाले आदिवासी बहुल झारखंड के विधानसभा चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब हरियाणा के चौंका देने वाले परिणामों ने इन दोनों राज्यों के चुनावों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र में विरोधाभास साफ जाहिर हैं। एक तरफ तो भाजपा, एकनाथ शिंदे सरकार, जो भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग तथा लोक-लुभावन योजनाओं के नाम पर राजकोष को खाली कर देने के आरोपों से जूझ रही है, को समर्थन दे रही है। वहीं बिडम्बना यह है कि झारखंड में भाजपा सत्ता में आने के लिये जे.एम.एम. सरकार पर यही आरोप लगा रही है।

- **महाराष्ट्र में भाजपा के पास शरद पवार व उद्धव ठाकरे जैसा करिश्माई नेता भी नहीं है। हालांकि भाजपा ने शरद पवार को कमज़ोर करने के लिए अजित पवार का और उद्धव ठाकरे को कमज़ोर करने के लिए एकनाथ शिंदे का प्रयोग किया, पर, उसे सफलता नहीं मिली।**
- **जबकि, हरियाणा में भाजपा का सामना धरातल पर बिखरी हुई व गुटबाजी से त्रस्त कांग्रेस से था, यही वजह रही कि कांटे की टक्कर में भाजपा ने जीत हासिल कर ली।**

हरियाणा में, भाजपा ने काँटे की टक्कर के तहत बिखरी हुई कांग्रेस को मात दे दी थी। उसका आंशिक कारण तो यह रहा कि कांग्रेस, भाजपा से कुल 22,000 वोटों के अन्तर से 9 सीटें हार गई, जिसमें इंडियन नैशनल लोक दल (आई.एन.एल.डी.) से हारी सीट भी शामिल हैं। लेकिन महाराष्ट्र एवं झारखंड की चुनावी स्थितियाँ पूरी तरह भिन्न हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस, गठबंधन में जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार एवं झारखंड में हेमन्त सोरेन की टक्कर के करिश्माई नेता भाजपा के पास नहीं है, इसीलिये भाजपा पूरी तरह से नरेन्द्र मोदी की छवि और अमित शाह की राजनैतिक चतुराई पर भरोसा करने के लिए मजबूर है।

महायुति गठबंधन में अजित पवार सबसे कमज़ोर कड़ी माने जाते हैं। अभी हाल ही तक, वे अपने चाचा शरद पवार के गुट में लौटने के लिये, उनसे समझौता वार्ता करने की कोशिश कर रहे थे। जब वे एन.सी.पी. को तोड़कर, भाजपा के पक्ष में गये थे, उस समय ई.डी. 80,000 करोड़ रूपए के सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ जाँच करने वाला था। लेकिन उनकी सारी परेशानियाँ भाजपा में शामिल होने के बाद समाप्त हो गईं। दरअसल, अजित पवार का प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों में ही है, जबकि शरद पवार का जनाधार व्यापक और मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनावों में, अजित पवार जैसे-तैसे एक सीट जीत पाये थे तथा उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले से बारामती सीट पर बुरी तरह हार गई थीं।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिव सेना लोकसभा चुनाव में 7 सीटें तथा भाजपा मात्र 9 सीटें जीत पाई थी। शिंदे गुट, लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर, अब सीटों के आनुपातिक आवंटन पर जोर दे रहा है। लेकिन चुनावों की घोषणा होते ही, भाजपा ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिये हैं तथा शिंदे और पवार गुट को दरकिनार कर दिया है। बताया जाता है कि भाजपा ने दिल्ली में शिंदे को यह स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा ज्यादा सीटें प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है क्योंकि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर तथा देवेन्द्र फड़नवीस उनका अधीनस्थ उप मुख्यमंत्री बनाकर, एक बड़ी कुर्बानी दी है। भाजपा यह दलील देती है कि लोकसभा चुनावों में शिंदे गुट को ज्यादातर वोट उत्तर भारत के प्रवासियों से मिले थे, जो परम्परागत रूप से मुम्बई तथा अन्य क्षेत्रों में भाजपा का मजबूत जनाधार हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एडिशनल एस.पी. ने 34 लाख में राजीनामा कराया- डी.जी. जाँच करें

जयपुर, 25 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर के गंगापुर थाने में दर्ज मामले में बिना जांच अधिकारी होते हुए, तत्कालीन स्थानीय एडिशनल एस.पी. की ओर से 34 लाख रुपए में पक्षकारों के बीच राजीनामा कराने के मामले में डी.जी.पी. को जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से वर्दी में नोटों के साथ बैठकर पक्षकारों में राजीनामा कराने को गंभीर माना है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी

- **हाई कोर्ट ने कहा, एडिशनल एस.पी. जाँच अधिकारी नहीं थे, पर वर्दी में नोटों के साथ पक्षकारों के साथ बैठकर समझौता कराया, यह गंभीर मामला है।**

का मध्यस्थता कराना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं माना जा सकता। ऐसे में डी.जी.पी. से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मामले की पुनः जांच कराएं अन्यथा पूर्व में तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे एडिशनल एस.पी. की सेवा पुस्तिका में लगाया जाए। इसके साथ ही, अदालत ने मामले के आरोपी पवन कुमार को जमानत पर रिहा करने को कहा है। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्व अधिकारी-अधिशाषी अधिकारी परीक्षा निरस्त

आर.पी.एस.सी. ने हाईटैक डिवाइस से नकल की पुष्टी होने पर यह निर्णय लिया

- **अतिरिक्त महानिदेशक एस.ओ.जी. ने 28 अगस्त की रिपोर्ट में आयोग को बताया कि परीक्षा की गोपनीयता के संबंध में गंभीर तथ्य सामने आये हैं।**
- **समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा 23 मार्च 2021 को होगी।**

अजमेर, 25 अक्टूबर (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के आयोजन के दौरान गोपनीयता भंग होने की जानकारी के बाद, राजस्व अधिकारी ग्रेड- द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 (14 मई 2023) को निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा के बारे में प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयोग ने 12 जून 2024 को शिकायतों की जांच के लिए ए.टी.एस. एवं एस.ओ. जी. को लिखा था। आयोग अब समस्त आवेदित अभ्यर्थियों के लिए 23 मार्च 2025 को पुनः परीक्षा का आयोजन करेगा।

आयोग सचिव के अनुसार, आयोग ने पाया कि परीक्षा आयोजन के दौरान ही कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर वांछित शुचिता का पूर्ण अभाव रहा है। कई अभ्यर्थियों द्वारा ब्लूटूथ से नकल करने के संबंध में दर्ज तीन प्राथमिक रिपोर्ट, उनके अनुसंधान उपरान्त, अपराध प्रमाणित पाये जाने पर स्पष्ट हुआ है कि राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) परीक्षा, 2022 (परीक्षा 14 मई 2023) की गोपनीयता खंडित हुई है। इसीलिए आयोग ने राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2022 को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया है।

आयोग द्वारा 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ स्वायत शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2022 में 1,96,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी सूची में कुल 311 अभ्यर्थी सम्मिलित थे।

दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों के संदिग्ध प्रतीत होने पर आयोग ने भी 02 अगस्त 2024 से दिनांक 08 अगस्त 2024 तक अनेक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच कर पूछताछ नोट तैयार किया और 14 अगस्त 2024 को अतिरिक्त महानिदेशक, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. को अग्रिम अनुसंधान करने के लिए लिखा था। इस क्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., राजस्थान, जयपुर ने 28 अगस्त 2024 को आयोग को अवगत कराया है कि उक्त परीक्षा आयोजन तिथि के दौरान परीक्षा की गोपनीयता के सम्बन्ध में गंभीर तथ्य सामने आये हैं। नकल के इसी प्रकरण में 24 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त एस.ओ.जी., जयपुर ने भी एस.ओ.जी. थाना जयपुर में 19 अक्टूबर 2024 को एफ.आई.आर. संख्या 66/2024 दर्ज की गई है एवं अनेक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।

क्या सिद्दीकी की हत्या के लिए हथियार पाकिस्तान से आए थे?

मुम्बई पुलिस को शक है कि हथियार ड्रोन के जरिए भेजे गए थे

मुंबई, 25 अक्टूबर। महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के दौरान हत्यारों के पास पांच अलग-अलग तरह की पिस्तौलें थीं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मामले में गिरफ्तार आरोपी राम कनौजिया के घर से एक पिस्तौल मिली है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मुंबई पुलिस ने संदेह जताया है कि ये पिस्तौलें पाकिस्तान से आई हैं। पुलिस को शक है कि ये ड्रोन के जरिए भेजी गई हैं। इन हथियारों की तस्वीरें राजस्थान पुलिस को भी भेजी गई हैं।

पुलिस के मुताबिक, पिस्टल रायगढ़ जिले के प्लसपे नाम की जगह से बरामद की गई है, जहां पर आरोपी राम कनौजिया का किराए का घर है। पुलिस को इस मामले में अब कुल 4 पिस्टल मिल चुकी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान पता चला कि हत्यारों के पास कुल 5 अलग-अलग तरह की पिस्टल थी।

- **मुम्बई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि हथियारों की तस्वीरें राजस्थान पुलिस को भी भेजी गई हैं।**
- **मुम्बई क्राइम ब्रांच को जाँच के दौरान पता चला कि हत्यारों के पास 5 अलग-अलग तरह की पिस्तौलें हैं। पुलिस चार पिस्तौलें बरामद कर चुकी है।**

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शूटर्स के मोबाइल को जब खंगाला गया तो उनमें पिस्तौलों की तस्वीरें मिली थीं। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच अन्य पिस्तौल ढूंढ ने में लग गई। मुंबई क्राइम ब्रांच को ऑस्ट्रेलिया मेड ब्रेटा पिस्तौल की तलाश है।

पुलिस के अनुसार, हरियाणा के रहने वाले गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के निवासी धर्मराज कश्यप के साथ आरोपी शिवकुमार गौतम ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी, जबकि पुणे के प्रवीण लोनकर के भाई शुभम का संबंध कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से है। उसने और अन्य आरोपियों ने हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी और शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी।

हत्या से पहले सिद्दीकी की सुरक्षा में मौजूद पुलिस अधिकारी पर मिर्च पाउडर फेंका गया था। वहीं, पुलिस के अनुसार, पुणे के एक स्क्रैप डीलर हरीश कुमार निसाद ने हत्या के लिए वित्तीय मदद दी थी। मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम के साथ ही मुख्य आरोपी शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर फिलहाल फरार हैं।

पुलिस सूत्रों बताया कि मुख्य आरोपी जीशान अख्तर अन्य सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसने काम पूरा होने पर उन्हें मोटी रकम और फॉरेन टूर का वादा किया था।

'विभागीय कार्यवाही लंबित होने पर विदेश यात्रा से नहीं रोक सकते'

जयपुर, 25 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि विभागीय कार्यवाही का लंबित होना, किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है, जिसमें विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने नीरज सक्सेना की याचिका पर बेटे से मिलने सिंगापुर जाने की सशर्त अनुमति दी।**

के अनुसार ही विदेश जाने से वंचित किया जा सकता है। विदेश जाने की स्वतंत्रता का सामाजिक महत्व है, यह महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक उसके बेटे से मिलने के लिए सिंगापुर जाने की सशर्त अनुमति भी दे दी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश नीरज सक्सैना की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध'

नोबल पुरस्कार विजेता कोरिअन लेखक की किताब कोरिया में ही प्रतिबंधित

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। "कोरिअन हैरल्ड" की चाई जाँग हून ने सिओल से खबर दी है कि दक्षिण कोरिया की उपन्यासकार हन कांग को 2024 का साहित्य का नोबल पुरस्कार मिलने के बाद देश भर में उल्लास का माहौल है, किन्तु, इस सबके बीच कांग की एक किताब को लेकर भारी वाद विवाद छिड़ गया है, जिसे "युवाओं के लिए हानिकारक" माना जा रहा है।

- **किताब में बच्चों को आरम्भ से ही सैक्स एजुकेशन देने की बात कही गई है, जो सारे विश्व में सराही जा रही है, पर, कोरिया के परम्परावादी खेमों ने इस किताब का सख्त विरोध किया है और इस किताब को उन स्कूलों व पुस्तकालयों में प्रतिबंधित कर दिया है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं।**

विवाद उस समय शुरू हुआ, जब यह पता चला कि, गत वर्ष ग्याँगी प्रांत के तकरीबन 2490 एलिमैन्टरी, मिडिल व हाई स्कूलों की लाइब्रेरी से जो 2528 किताबें हटाई गई थीं, उनमें कांग की किताब "द वैजिटेरियन" भी शामिल थी। हटाई गई सभी पुस्तकों को छात्रों के लिए हानिकारक माना गया था।

इन पुस्तकों में हन कांग की किताब ही नहीं बल्कि, एक और नोबल पुरस्कार विजेता लोक होज़े सारामागो की पुस्तक "ब्लाइन्डनैस" माइकल रोइज़न की, "यू: द ओनर्स मैनुअल", जिसे जर्मनी में "साइन्स बुक ऑफ द ईयर" अवॉर्ड मिला था तथा टाइम्स एजुकेशनल सप्लिमैंट्स सीनियर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड जीतने वाली, सूजन मैरडिथ की "वॉट्स हैपनिंग टु मी" शामिल है। आखिरी दो किताबें, किशोरों के लिए सैक्स एजुकेशन तथा मानव शरीर के बारे में हैं।

यह कदम तब उठाया गया, जब ग्याँगी प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ एजुकेशन एक रूढ़िवादी एन.जी.ओ. की सलाह पर स्कूलों को पुस्तकों के बारे में मैमो भेजा। एन.जी.ओ. ने स्कूलों को सैक्स संबंधी किताबें हटाने की सलाह दी थी। तथापि, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज़्म के तहत आने वाली पब्लिकेशन इण्डस्ट्री प्रमोशन एजेन्सी ऑफ कोरिया ने हटाई गई किताबों में से केवल एक किताब को युवाओं के लिए हानिकारक माना।

हान की, लिटरेचर में नोबल की ऐतिहासिक जीत के बारे में स्कूलों और घरों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई।

दो बेटियों की माँ, ली ने कहा, "मेरी बेटी, जो आठवीं कक्षा में है, ने कहा कि वो हान की किताब "द वैजिटेरियन" पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके टीचर्स ने उसे "ह्यूमन एक्ट्स" नाम की दूसरी किताब पढ़ने की सलाह दी। ली ने आगे कहा, "द वैजिटेरियन" को मेरी बेटी की उम्र के बच्चों के लिए अनुपयुक्त बताया गया।

माताओं के एक लाइन कैफे में एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुशांत डैथ केस में रिया चक्रवर्ती को राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सप्ताह के शुरु में सी.बी.आई. तथा महाराष्ट्र की उस अपील को "सारहीन" बताते हुये खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती तथा भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ जारी किये गये "लुक आउट सर्कुलर्स" (एल.ओ.सी.) को रद्द कर दिया गया था।

रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती तथा उनके पिता लेफ्टिनेन्ट कर्नल इन्द्रजीत चक्रवर्ती को "लुक आउट सर्कुलर" सी.बी.आई. द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जाँच के सिलसिले में जारी किये गये थे।

- **सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. द्वारा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और पिता रिटायर्ड सैन्य अधिकारी इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी "लुक आउट सर्कुलर" को रद्द कर दिया।**

एल.ओ.सी. को रद्द कर देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सी.बी.आई. की याचिका को "सारहीन" बताते हुये, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई तथा के.वी. विश्वनाथन की बैंच ने कहा कि जाँच एजेंसी इस शीर्ष अदालत में केवल इसलिये आई है, क्योंकि आरोपी हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं।

इसके बाद, बैंच ने सी.बी.आई. की याचिका खारिज कर दी। सी.बी.आई. ने इनके खिलाफ एल.ओ.सी. उस समय जारी किये थे, जब राजपूत के परिवार ने पटना में एक एफ.आई.आर. दर्ज करके, राजपूत की मृत्यु की जाँच की माँग की थी।

उच्च न्यायालय ने ये एल.ओ.सी. फरवरी 2024 में रद्द कर दिये थे तथा कहा था कि सी.बी.आई., एल.ओ.सी. जारी करने के कारण नहीं बता पाई है।

विख्यात वैज्ञानिक रोहिणी गोड़बोले का निधन

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत करने वाली प्रमुख आवाज़ों में से एक भौतिक विज्ञानी रोहिणी गोडबोले का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थीं।

पद्म श्री से सम्मानित गोडबोले 25 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र से जुड़ी रहीं। उन्होंने 2018

- **प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया।**

में सेवानिवृत्ति के बाद मानद प्रोफेसर के रूप में काम किया है। पुणे में जन्मी गोडबोले एसपी कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), बॉम्बे की पूर्व छात्रा थीं। बारह नवंबर 1952 को जन्मी गोडबोले ने 1979 में अमेरिका के स्टोनी ब्रूक्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया।

प्रधानमंत्री ने गोडबोले के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने शोक संदेश में कहा, रोहिणी गोडबोले जी के निधन से बहुत दुःख हुआ। वह एक अग्रणी वैज्ञानिक और नवोन्मेषक थीं, जो विज्ञान की दुनिया में अधिक महिलाओं की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रैस काउन्सिल ऑफ इंडिया एक्ट में और दम डालने की जरुरत है

प्रैस काउन्सिल ऑफ इंडिया की मीटिंग में सदस्यों ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया, पर, अध्यक्ष ने इसमें "असहमति पत्र" भी संलग्न किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केन्द्र सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए नैशनल कानून बनाने और लागू करने का आग्रह किया है। हालांकि इसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने इस पर असंतोष जताया है। ज्ञातव्य है कि प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन संसद ने किया है।

पत्रकारों की गिरफ्तारी, गैर कानूनी तरीके से बन्दी बनाने और धमकाने के खिलाफ यह प्रस्ताव पी.सी.आई. सदस्य गुरबीर सिंह ने बनाया था, जिसे 27 सितम्बर को बहुमत से स्वीकार किया गया था।

इसमें प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया एक्ट को ज्यादा शक्तियां देने की मांग की गई है, ताकि यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के लिए उभर रही चुनौतियों व खतरों से निपटने में सक्षम हो सके।

सिंह लिखते हैं कि अभी पी.सी.आई. सिर्फ सलाहकारी आदेश ही दे सकती है, जो बाध्यकारी नहीं होता है, इसलिए उन तत्वों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में मांग की गई है कि पुलिस के लोगों को लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उनके साथ आचरण के नियम बनाए जाएं।

- **प्रैस काउन्सिल की मीटिंग में पत्रकार गुरबीर सिंह ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकारें काउन्सिल के आदेश को उपदेश मात्र मानकर उपेक्षित कर देती हैं तथा आदेश की परवाह नहीं करती हैं और पत्रकारों को धमकाती हैं।**
- **प्रस्ताव में बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत में 5 पत्रकारों की हत्या हुई तथा 226 पत्रकारों को सरकारों, राजनेताओं ने और असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया।**

उदाहरण के लिए, एक पत्रकार की गिरफ्तारी से पूर्व संपादक या प्रकाशन से पुष्टि की जाए कि क्या संबंधित पत्रकार किसी विषय पर काम कर रहा था।

सिंह ने कहा कि उच्चस्तर से लेकर निम्नस्तर के कॉंस्टेबल तक, सभी के लिए गंभीर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाए और उन्हें पत्रकारों के साथ सम्मान से व्यवहार करना सिखाया जाए।

रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में देश भर में पत्रकारों की हत्या हुई हैं तथा 226 को राज्य सरकारों ने या असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है।

सिंह ने कहा कि प्राइवेट सर्वे के अनुसार भारतीय समाचार संघ गंभीर दबाव में काम कर रहे हैं। प्रैस फ्रीडम की जहां तक बात है, वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इन्डैक्स, 2024 में भारत का स्थान 180 देशों में 159 वां है।

प्रस्ताव में पत्रकारों से जुड़े कई मामलों का जिक्र है, जिनमें समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक पर दिल्ली पुलिस की रेड भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को न्यूजक्लिक के 86 पत्रकारों पर रेड की थी। न्यूज क्लिक पोर्टल के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन चीफ अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली के दंगों को कवर कर रहे कारवां मैगज़ीन के पत्रकार पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था।

इस रिपोर्ट पर पी.सी.आई.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सार-समाचार

मोशन में दीपावली का त्यौहार मनाया

कोटा (निसं)। मोशन एजुकेशन की ओर से शुक्रवार को दीपावली का पर्व उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान दीप जलाऐं, पटाखे चलाए और बच्चों ने शानदार म्युजिकल प्रस्तुतियां दी। मुख्य समारोह ध्रुव कैम्पस में हुआ। इसका उद्घाटन मोशन एजुकेशन के चेयरमैन सुरेंद्र विजय और डायरेक्टर सुशीला विजय ने किया। सीईओ और फाउंडर नितिन विजय, डॉ.स्वाति विजय, ज्वाइंट डायरेक्टर रामरतन द्विवेदी, अमित वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर डॉ.आशीष माहेश्वरी, जितेंद्र चंदवानी और ललित विजय ने भी समारोह में शिरकत की। चेयरमैन सुरेंद्र विजय ने विद्यार्थियों को दीपावली का महत्व बताते हुए कहा कि दीपावली का त्यौहार भगवान श्रीराम के चौदह साल वनवास काटने के बाद अपने घर अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद बच्चों ने एक से एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे-एकल और सामूहिक नृत्य, कविता पाठ, शायरी, गायन और भाषण पेश किए। समापन फाउंडेशन डिवीजन के स्टूडेंट्स के रैंप वॉक से हुआ। संचालन 12वीं बायोलॉजी की छात्रा श्रेया जयसवाल ने किया। मोशन के द्रोणा, दक्ष और कारपोरेट ऑफिस कैम्पस में भी दीपावली सेलिब्रेशन हुआ। इसमें स्टॉफ को मिठाई और उपहार वितरित किए। इस दौरान अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चों ने गीत-संगीत पर डांस कर त्यौहार का आनंद लिया। स्टाफ ने भी दीपावली महोत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

निरीक्षण के दौरान दूषित चाशनी मिली

कोटा, (निसं)। दीपावली व दशहरा मेले में पर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले इसके प्रदेशभर में लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिससे खाद्य सामग्री विक्रेता मिलावटी सामग्री नहीं बेच सकें। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जगदीश सोनी ने बताया कि कोटा में दिवाली के पहले 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत लगातार कोटा व कोटा के ग्रामीण इलाको में सघन कार्यवाही की गई। शुक्रवार को टीम ने कोटा शहर सहित सांगोद, देवलीमाँझी, केथुन पहुंच कर दर्जनों दुकानों का निरीक्षण कर कोटा बालिता रोड़ स्थित कहार मिल्क प्रोडक्ट्स, पाटन चौराहा स्थित कहार डेयरी, सांगोद स्थित ओम मिष्ठान भण्डार, अग्रवाल नमकीन एंड स्वीट्स, कैथून स्थित के.जी.एन.जोधपुर एंड स्वीट्स से 13 नमूने दही-2, पनीर-1, मावा-2,घी-1, क्रीम-1, दूध-2, मिल्क केक-1, बर्फी -2, मीठी नुक्ती-1 का एक नमूना लेकर, 72 किलो दूषित चासनी व 10 किलो सड़ी मिठाई नष्ट करायी। साथ ही एमएफटीएल चल प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों के 22 नमूनों की जांच की गई। लिए गए सभी नमूनों को जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया गया, रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

'सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा मे खाद, बीज, बिजली, पानी मुहैया कराए'

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर किसानों को रबी की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा मे खाद, बीज, बिजली, पानी मुहैया कराए जाने की मांग की है। मनोज दुबे ने कहा की प्रदेश का किसान रबी की फसल बुआई के लिए खाद बीज बिजली पानी के लिए परेशान हो रहा है। किसानों को ना डीएपी मिल रही है, ना बीज ओर ना बिजली-पानी जिससे किसानों की रबी की फसल की बुआई बाधित हो रहीं है। सरकार किसानों की मांग के अनुरूप किसानों को सही गुणवत्ता वाली खाद और बीज उपलब्ध कराऐं। व खाद एवं बीज की किल्लत दूर करें। मनोज दुबे ने कहा की सरकार किसानों से चुनाव मे 24 घंटे बिजली देने की बात करती हैं। लेकिन किसानों को 12 घंटे भी बिजली नहीं दे रही है। किसानों को बड़ी मुश्किल से मात्र 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। किसानों को नहरी पानी मिलने मे भी काफी समस्याएं हैं। क्योकि नहरों व वितरिकाओं की सफ़ाई सही प्रकार से नहीं हुई है। मनोज दुबे ने कहा की किसानों को खाद, बीज, बिजली, पानी की समस्या के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा मे खाद, बीज, बिजली, पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा सड़कों पर उतर कर सरकार व प्रशासन का विरोध करेगी।

आबकारी विभाग ने बकायादार की 2.43 हैक्टेयर जमीन कुर्क की

कोटा, (निसं)। राज्य में बकाया वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को आबकारी विभाग ने एक बकायादार की 2.43 हैक्टेयर जमीन कुर्क की गई है। इस बकायादार पर विभाग के वर्ष 2021 से एक करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि चल रही है। इस पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन कोटा नरेश मालव व जिला आबकारी अधिकारी भंवरलाल जनागल के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई। सहायक आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार प्रजापत ने बताया कि एमनेस्टी योजना 2024 के अन्तर्गत बकायादारों को राज्य सरकार द्वारा मूल राशि की आधी राशि जमा कराने की छूट दी गई है। इस पर भी जिन बकायादारों द्वारा राशि जमा नहीं करवाई जा रही है उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत बाकीदार प्रेमचन्द मेहता पुत्र छीतरलाल मेहता निवासी ग्राम कुराड़ तहसील कनवास जिला कोटा की ग्राम कुराड़ में स्थित 2.43 हैक्टेयर कृषि भूमि कुर्क की गई। कार्यवाही में आबकारी निरीक्षक विपीन वेदजीत मीणा, चेतन लाल रेगर, प्रदीप सिंह मीणा, पुष्पेन्द्र सिंह, सुखवेन्द्र सिंह व प्रहराधिकारी पृथ्वीराज सिंह मीणा मय जाप्ता शामिल रहे।

अन्नकूट महोत्सव के कार्ड का विमोचन

कोटा, (निसं)। आदर्श अग्रवाल सेवा संस्था एवं प्रादेशिक सेवारत वैश्य सेवा संस्था द्वारा आयोजित अन्नकूट महोत्सव के कार्ड का विमोचन शुक्रवार को समाजसेवी महेश गुप्ता द्वारा किया गया। संस्थान के अध्यक्ष हुकम मंगल ने बताया कि अग्रवाल सम्मेलन की ओर से रीको सामुदायिक भवन इन्द्र विहार पर अन्नकूट आयोजित किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे। कार्यक्रम में शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में समाजबंधु भाग लेंगे। इस मौके पर संस्था के 63 कार्यकारी सदस्य उपस्थित थे। जिसमें महेश गुप्ता, हुकुमचंद मंगल, अनिल गुप्ता, आरसी गुप्ता, राजेंद्र जैन, रमेश खंडेलवाल, कुंजबिहारी चित्तौड़ा, किशन चंद गुप्ता, बद्री विशाल गुप्ता, सुरेंद्र मोहन मित्तल, सीके पूर्व, सीताराम मंगल, तरसेम गर्ग, गिर्राज पोखरा, हनुमान अग्रवाल, मोहनलाल मित्तल, सोहनलाल मित्तल, सुरेश नाटाणी, महावीर प्रसाद जैन,अनूप सिंगला, मनोज गुप्ता, विजय बंसल उपस्थित रहे।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई

कोटा, (निसं)। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉ.रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉ.गोस्वामी ने निर्देश दिए कि जिले के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों के बाल वाहिनियों के ड्राईवर, कंडक्टर, हेल्पर एवं स्कूल स्टाफ के लिए पुलिस द्वारा एक विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें उन्हें ड्राइविंग के नियमों और सुरक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी विस्तार से प्रदान की जाएगी। इस प्रशिक्षण के बाद ड्राईवरों को एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा, ताकि बच्चों के परिजन भी उनके प्रशिक्षित होने के बारे में आश्वस्त हो सकें।

आठ प्रकरणों में पैरोल स्वीकृत

कोटा, (निसं)। पैरोल सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉ.रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 11 प्रकरण प्रस्तावित किए गए जिनमें से आठ प्रकरणों में पैरोल स्वीकृति दी गई। दो प्रकरण निरस्त किए गए जबकि एक प्रकरण में पुन: रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम सिटी कारागृह अधीक्षक एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

दीवाली लाइटिंग का शुभारम्भ किया

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को सीकर रोड व्यापार मंडल द्वारा की जा रही बाज़ार साज-सज्जा में लाईट डेकोरेशन का शुभारम्भ किया। इस मौक़े पर हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य भी मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रवासियों को त्योहारों की बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की पूरी टीम विद्याधर नगर के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है और तेज़ी से विकास के काम शुरु किये जा रहे है।

शिक्षा मंत्री ने महिला मजदूरों के बीच बैठकर दाल-रोटी खाई

कोटा, (निसं)। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरूवार को देवली खुर्द गांव में आयोजित सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर में शामिल होने पहुंचे थे। रास्ते में भावपुरा गांव में शिक्षा मंत्री मजदूर महिलाओं से मिले और बड़ी सहजता के साथ जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनी।

महिलाओं से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने उनसे पूछा कि आज टिफिन में क्या है। इस पर महिलाओं ने बताया कि टिफिन में दाल और रोटी है। मंत्री ने जब कहा कि मुझे खिलाओ तब एक मजदूर महिला बोली आप मंत्री हैं हमारा हाथ का बनाया भोजन खाएंगे। इस पर मंत्री ने कहा कि मैं खाऊंगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री उन महिला मजदूरों के साथ बैठ गए और उनके टिफिन से दाल रोटी खाई। मंत्री को अपने हाथों से बना भोजन करते देख महिलाएं बहुत प्रसन्न थी। भोजन कराने वाली महिला ने कहा कि सभी नेता हर बार चुनाव में बस्ती में वोट मांगने तो आते हैं। लेकिन इस तरह से हम गरीब लोगों के हाथ से बना खाना किसी नेता ने नहीं खाया। ''ये छै माह जैसा गरीब लोगान का असली नेता।''

1 करोड़ 61 लाख रुपए से निर्मित दो सड़कों का लोकार्पण:- शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में एक करोड़ 61 लाख 56 हजार रुपए की लागत से निर्मित 2 सड़कों का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने बिशनीया खेड़ी गांव में 80.37 लाख रुपए की लागत से निर्मित डेढ़ किलोमीटर लंबी रावली से बिशनीया खेड़ी मिसिंग लिंक रोड तथा 81 लाख की लागत से निर्मित डेढ़ किलोमीटर लंबी भावपुरा से देवली मिसिंग लिंक रोड का लोकार्पण किया। दोनों सड़कों का निर्माण कृषि उपज मंडी समिति (विशिष्ठ श्रेणी) रामगंजमंडी के अंतर्गत कराया गया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत हो गई हैं, आने वाले समय में 5 और स्वीकृत कराई जाएंगी। पांच साल में कोई भी गांव सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। कार्यक्रम में प्रधान कलावती मेघवाल नीता वसीटा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

आधुनिक शौचालय का लोकार्पण:- शिक्षा मंत्री ने देवली खुर्द में 10 लाख की लागत से बने आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया। शौचालय का निर्माण लोकसभा स्पीकर के सांसद कोष से 10 लाख रुपए देकर ग्रामवासियों की मांग पर करवाया गया। परिसर में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग आधुनिक शौचालय का निर्माण किया गया है।

प्रवेश से वंचित 9 छात्रों का एडमिशन करवाया:- सरकार आपके द्वारा समस्या समाधान शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को देवली खुर्द में आयोजित जनसुनवाई के दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रवेश से वंचित 9 छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा से बात कर महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। साथ ही, दोनों वर्गों को बालिका से सह शिक्षा में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव भेज कर स्वीकृत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शिक्षा मंत्री को राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी के प्राचार्य संजय सिंह गुर्जर का पत्र लेकर पहुंचे इन 9 छात्र-छात्राओं ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा की अनुपालन में राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी (सह शिक्षा कला संकाय) में दो अतिरिक्त वर्ग स्वीकृत किए गए थे जिनके अंतर्गत केवल बालिकाओं को ही प्रवेश की अनुमति है। जिससे छात्र इनमें प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।

गत सत्र में भी अतिरिक्त आयुक्त के पत्र के पश्चात अतिरिक्त वर्ग की शेष रिक्त सीटों पर फीस जमा करा चुके छात्रों का प्रवेश हो पाया था। इस वर्ष भी छात्र पुन: प्रवेश से वंचित हैं। अत: इन दोनों वर्गों को सह शिक्षा में परिवर्तित किया जाए तथा प्रवेश से वंचित छात्रों को उक्त अतिरिक्त वर्ग की सीटों पर प्रवेश दिया जाए।

इस पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए शिक्षा मंत्री ने अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा से बात कर महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। शिक्षा मंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

कोटा विकास प्राधिकरण ने चन्द्रमोली आवासीय योजना लॉन्च की

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा आवासीय योजना लॉन्च की गई है। योजना की लॉन्चिंग कार्यवाहक सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर कोटा डॉ.रविन्द्र गोस्वामी द्वारा की गई।

कोटा चन्द्रेसल में सोगरिया रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित इस योजना में ई.डब्ल्यू.एस. कैटिगरी के आवेदकों को रियायती शुल्क पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे।योजना में आवेदन के लिए 25 अक्टूबर से 26 नवंबर 2024 तक बैंक ऑफ बड़ौदा की यूआईटी शाखा से प्राप्त कर जमा किया जा सकता है। आवेदन के लिए 2000 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क है। इसके अलावा अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग पंजीयन शुल्क भी है।

यह शुल्क 22 हजार से 4.84 लाख रुपए तक है।इनमें अलग-अलग साइज के भूखंड हैं। जिनमें 436 स्क्वायर फीट से लेकर 4358 स्क्वायर फीट तक है। इनकी कीमत 2.20 लाख रुपए से लेकर 48.41 लख रुपए तक है। कोटा के उपनगरीय स्टेशन सोगरिया के पास में बनाई इस स्कीम में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी ए व बी, एचआईजी 1, 2 व 3 कैटिगरी के अलग-अलग साइज में भूखंड हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि यह योजना काफी प्रभावशाली है और इस योजना मैं निम्न आय वर्ग के लोगों को रियायती दर पर भूखंड दिए जाएंगे। कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव कुशल कोठारी ने बताया कि यह योजना कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा पूरी तरीके से विकसित की गई है। इसमें कोटा विकास प्राधिकरण समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है।

योजना की लांचिंग के दौरान कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव कुशल कोठारी, निदेशक वित्त डॉ. नीतू सिंह, उप सचिव हर्षित वर्मा, मालविका त्यागी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर शर्मा, निदेशक अभियांत्रिकी रविन्द्र माथुर अधीक्षण अभियंता नवीन सिंघल निदेशक विधि अधिकारी वीरेंद्र यादव सहित प्राधिकरण के कई अधिकारी उपस्थित रहे।

दिव्यांग के एक वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में एक हाथ और एक पांव वाले दिव्यांग अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर केन्द्र सरकार, प्रमुख चिकित्सा सचिव और सिफू निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती की नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। सीएम एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पंकज कुमार खियानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 5 मई, 2023 को फार्मासिस्ट के 2859 पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण देते हुए 111 पद आरक्षित रखे गए। वहीं यह शर्त लगाई गई कि केन्द्र सरकार की ओर से 4 नवंबर, 2021 को जारी गजट नोटिफिकेशन में दर्शाये दिव्यांग वर्ग को ही इसका लाभ मिलेगा। याचिका में कहा गया कि वह एक हाथ और एक पांव से दिव्यांग है, लेकिन केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन में इस वर्ग के दिव्यांगों को फार्मासिस्ट भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि होम्योपैथी में फार्मासिस्ट कम क्लर्क के पदों पर दिव्यांग के इस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है और उनका काम भी सामान्य फार्मासिस्ट के समान ही होता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में पदोन्नित से भरे जाने वाले चीफ फार्मासिस्ट पद के लिए भी इस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है। याचिका में केन्द्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह नोटिफिकेशन समानता के अधिकार की अवहेलना करता है। एक समान लोगों पर अलग-अलग नियम लागू नहीं किया जा सकते हैं। वहीं एक पांव और एक हाथ से दिव्यांग व्यक्ति फार्मासिस्ट का काम आसानी से कर सकता है। इसलिए केन्द्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और याचिकाकर्ता को फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।

अदालत ने 27 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने से इंकार किया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह तीन दिन के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने बाल कल्याण समिति की ओर से पीड़िता की उम्र का पुन: परीक्षण कराने के आदेश को रिकॉर्ड पर लिया है। जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश पीड़ित पक्ष की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि सामाजिक व मनोवैज्ञानित दबाव के कारण पीड़िता की जान का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। अदालत ने कहा कि पीड़िता को बालिका गृह में रखा जाए और होने वाले नवजात को अस्पताल में सुरक्षित रखा जाए। वहीं अदालत ने पीड़ित पक्ष नवजात को गोद देने के लिए एनओसी देने को कहा है। मामले में नवजात के डीएनए के दो नमूने लेकर पुलिस को सौंपे जाएगे और पीड़िता को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

याचिका में अधिवक्ता संगीता शर्मा ने बताया कि पीडिता दुष्कर्म के कारण गर्भवती हो गई है। यदि उसने संतान को जन्म दिया तो उसकी सामाजिक और मानसिक स्थिति खराब होगी। ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर गर्भपात से उसकी जान के जोखिम की बात कही।

वहीं अदालत के सामने आया कि पीडिता की एक जांच में उम्र 12 साल आई है। जबकि एक्सरे के माध्यम से की गई दूसरी जांच में उसकी उम्र 19-20 साल बताई गई है। वहीं बाल कल्याण समिति ने कहा कि पीड़िता की उम्र का पुन: परीक्षण कराने का निर्णय लिया है।

इस पर अदालत ने समिति के निर्णय को रिकॉर्ड पर लेते हुए गर्भपात की अनुमति देने इनकार कर दिया है।

जनता विकास के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार के साथ : भजनलाल शर्मा

- लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि : मदन राठौड़
- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खींवसर, संलुबर और चौरासी विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित किया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज खींवसर, संलुबर और चौरासी विधानसभा उप चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने खींवसर से भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा, संलुबर से शांति देवी मीणा और चौरासी से कारीलाल ननोमा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ विजय दिलाकर विधानसभा में भेजने का आव्हान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास के कार्य करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने का कार्य किया है। भाजपा सरकार खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राइजिंग राजस्थान के तहत अकेले संलुबर विधानसभा क्षेत्र में 250 करोड़ के 6 एमओयू साइन किए गए है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र का विकास करना है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के उत्पीडन, गुंडागर्दी और अपराध पर लगाम लगाने का भी कार्य किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है, इस जनता जनार्दन को कुछ लोग बहलाकर विधायक या सांसद बन गए लेकिन पद पाने के बाद इन लोगों ने इस जनता जनार्दन को ही भूला दिया। अब समय आ गया है कि इन लोगों को वापस खास से आम बना दिया जाए।

सीएचए व सीएचओ को बोनस अंक देने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड के समय संविदा पर दो साल से भी कम काम करने वाले कोविड हैल्थ वर्कर व कोविड हैल्थ ऑफिसर को कार्य अनुभव के 15 बोनस अंक देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के निदेशक से जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश लोकेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 अप्रैल, 2023 को अधिसूचना जारी कर कोविड में दो साल से कम काम करने वालों को 15 बोनस अंक देने का प्रावधान किया। याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान गलत है, क्योंकि इससे तो कोविड में एक दिन काम करने वाला अभ्यर्थी भी बोनस अंक का पात्र हो जाएगा। जबकि सीएचए व सीएचओ का काम नर्सिंग के समान नहीं है। सीएचए व सीएचओ को बोनस अंक देने से याचिकाकर्ता नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 की अस्थाई वरीयता सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि वे पिछले 7-8 साल से नियमित तौर पर नर्सिंग का काम कर रहे हैं। उन्हें बोनस अंक देने से याचिकाकर्ताओं के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए दो साल से कम काम करने वाले सीएचए व सीएचओ को बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जाए।

जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में विविध कला प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन

- रंगोली मांडना समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन

कोटा, (निसं)। दीपावली पर्व के मौके पर रानपुर स्थित जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में विविध कला प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया।

कुलसचिव डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन मे शुक्रवार को असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.सोनल गुप्ता के संयोजन में मेहन्दी प्रतियोगिता, गिरजा मीणा के संयोजन में रंगोली प्रतियोगिता व होटल प्रबन्धन विभाग के प्रभारी भारत शर्मा के निर्देशन में पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें मेहन्दी प्रतियोगिता में प्रिया मीणा ने प्रथम, डॉली मीणा ने द्वितीय, पायल वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इसी क्रम में मांडना प्रतियोगिता में प्रिया मीणा ने प्रथम, महक ने द्वितीय, श्याम रेखा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा पाक-कला प्रतियोगिता में अक्षिता व प्रीति ने संयुक्त रूप से प्रथम, माहिन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मण्डल में डॉ.सावित्री सिंहवाल, प्रो.गोपाल सिंह, डॉ.पूनम सिंह आदि सम्मिलित थे।

विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन आर.डी. मीणा, प्रेसिडेण्ड (कुलपति) प्रो.डी.पी. तिवारी व विश्वविद्यालय प्रबन्धन मण्डल के सदस्य प्रो.गोपाल सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किये। इस अवसर पर चेयरपर्सन आर.डी. मीणा ने सभी प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस प्रकार की पाठ्यसहगामी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रेरित किया।

प्रेसिडेण्ड (कुलपति) प्रो. डी.पी. तिवारी ने सभी विजेता प्रतियोगियों को बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। इन गतिविधियों का आयोजन सांस्कृतिक आयोजन समिति की प्रभारी डॉ. सुमन भारती मीणा के संयोजन में किया गया।

इसी अवसर पर विश्वविद्यालय अन्तर्गत विज्ञान विभाग में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा औद्योगिक इकाईयों में भ्रमण करते हुए उनकी कार्यविधियों का अवलोकन किया, जो कि उनके पाठ्यक्रम अन्तर्गत प्रायोगिक गतिविधियों में सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का आयोजन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद आशिद, डॉ. सोनल गुप्ता, डॉ. पूनम सिंह व जयराम मीणा द्वारा किया गया।

मिचेल सैंटनर के सामने पस्त नजर आए भारतीय बल्लेबाज

301 की बढ़त के साथ न्यूजीलैंड

पुणे, 25 अक्टूबर। मिचेल सैंटनर (सात विकेट) की घातक गेंदबाजी के बाद कप्तान टॉम लेथम (86) रनों की जूझारू पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को भारत को पहली पारी में 156 के स्कोर पर समेट कर दूसरी पारी में पांच विकेट पर 198 रनों के साथ 301 की बढ़त हासिल कर मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली हैं।

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी कप्तान टॉम लेथम और डेवन कॉन्वे की सलामी जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत की। 10वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने डेवन कॉन्वे (17) को पगबाधा आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद आर अश्विन ने विल यंग (23) को पगबाधा आउट कर पवेलियन भेज दिया। रचिन रविंद्र (नौ), डैरिल मिचेल (18) तथा टॉम लेथम (86) को वॉशिंगटन ने अपना शिकार बनाया। दिन का खेल समाप्त होने के साथ न्यूजीलैंड ने 53 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 198 रन बना लिये थे और उसकी कुल बढ़त 301 रन हो गई है। टॉम ब्लंडल (नाबाद 30) और ग्लेन फिलिप्स (नौ) रन क्रीज पर थे। भारत की ओर आज के हीरो भी वॉशिंगटन सुंदर रहे। उन्होंने 19 ओवर में 56 रन देकर चार विकेट लिये। वहीं आर अश्विन को एक विकेट मिला। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत पहली पारी में 156 के स्कोर पर समेटते हुए 103 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। कल के एक विकेट पर 16 रन से आगे खेलते हुए भारत को आज शुभमन गिल (30) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद अगले बल्लेबाज विराट कोहली (एक) रन बनाकर पवेलियन लौट गये। न्यूजीलैंड के स्पिनरों की कसी हुई गेंदबाजी के सामने भारत ने यशस्वी जायसवाल (30), सरफराज खान (11) और ऋषभ पंत (18) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। आर अश्विन (चार) रन बनाकर आउट हुये।

विराट कोहली की खराब फॉर्म जारी

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खराब शॉट खेलकर आउट हुए। कोहली खेल के सबसे लंबे प्रारूप में पिछले कुछ मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने 70 रन बनाए थे और दूसरे मैच में वह पहली पारी में सिर्फ एक रन बना सके, जिसके कारण उनके फॉर्म पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पूर्व गेंदबाज अनिल कुंबले का मानना है कि विराट कोहली को लंबे टेस्ट सीजन शुरू होने से पहले घरेलू क्रिकेट में खेलने का फायदा हो सकता था। पहली पारी में विराट कोहली मिचेल सैंटनर की फुलटॉस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।

भोजनकाल तक भारत ने सात 107 के स्कोर पर अपने सात विकेट गवां दिये थे। लगातार गिरते विकेटों के बीच रवींद्र जडेजा ने 46 गेंदों पर (38) रनों की जूझारु पारी खेली। उनके आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज आकाश दीप (छह) रन बनाकर आउट हुए। निचलेक्रम में बल्लेबाजी के लिए आए वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 18 रन की पारी खेली। भारतीय टीम 45.3 ओवर में 156 के स्कोर पर सिमट गई।

सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश में राजस्थान को 4 कांस्य

जयपुर, 25 अक्टूबर। कोलकाता में शुक्रवार को संपन्न हुई नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने चार कांस्य पदक अपने नाम किए। राजस्थान के चारों खिलाड़ी सेमी फाइनल में हार गए थे। पदक विजेता खिलाड़ियों में तीन खिलाड़ी सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित राजस्थान स्क्वैश एकेडमी के हैं।

एकेडमी की संचालक सुरभि मिश्रा के अनुसार राजस्थान की दिव्यांशी जैन ने अंडर-13 गर्ल्स के क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु की दीपा देबीराम को 13-15, 11-4, 11-8, 11-9 से हराया लेकिन सेमी फाइनल में तमिलनाडु की ही गौशिका के हाथों 13-11, 8-11, 8-11, 6-11 से हार के साथ उन्हें कांस्य से संतोष करना पड़ा। अंडर-17 गर्ल्स में याशी जैन ने कांस्य पदक जीता। जोधपुर की याशी को सेमी फाइनल में टॉप सीड दिल्ली की अनाहत सिंह ने सीधे सेटों में 11-3, 11-1, 11-2 से शिकस्त दी। याशी ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु की आर्या द्विवेदी को 7-11, 11-7, 11-6, 9-11, 11-3 से हरा अंतिम चार में जगह बनाई थी।

लड़कों के अंडर-19 वर्ग में अवलोकित सिंह ने उत्तर प्रदेश के अंश त्रिपाठी को 11-9, 11-2, 8-11, 11-9 से हरा अंतिम चार में जगह बनाई लेकिन सेमी फाइनल में उन्हें महाराष्ट्र के अयान वजीरअली से 7-11, 7-11, 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह अंडर-17 वर्ग के क्वार्टर फाइनल में सुभाष चौधरी ने क्वार्टर फाइनल में रचित शाह को 11-5, 11-9, 11-2 से हरा सेमी फाइनल में प्रवेश किया।

RAJASTHAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER)
DURGAPURA, JAIPUR
Phone: 0141-2550229 (O) Phone & Fax: 0141-2550229 & 2550536
Email : director.rari@sknau.ac.in Mob.No. 9414639561
No.F.9( )/SKNAU/DIR-RARI/Estt.I/2024/2515 Dated: 25-10-2024
ADVERTISEMENT
Applications are invited for Two YP in Plant Breeding & Genetics and Plant Pathology at RARI, Durgapura-Jaipur. For details login the University website: sknau.ac.in
Raj.Samwad/C/24/7031 DIRECTOR

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि जिला खण्ड प्रथम बीकानेर
क्रमांक-2246 दिनांक-21/10/24
Notice Inviting Bid : 09/ 2024-25
Bid for the Construction of Govt. Ambedkar SC Boys Hostal at Dantore (Khajuwala) District Bikaner are invited from interested bidders upto 29.10.2024 [09:30 AM] to 12.11.2024 [06:00 PM] & Open date 13.11.2024 [11:00 AM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www. pwd.rajasthan.gov.in & eproc. rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 215.00 Lakh.
UBN No. PWD 2425WSOBO8668
Executive Engineer, PWD Distt. Dn-i, Bikaner
DIPR/C/10456/2024

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
क्रमांक :– जोविप्रा/2024–25/EE HQ/1468 दिनांक : 24.10.2024
:: ई–निविदा सूचना संख्या –मुख्यालय/29/2024–25 ::
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत संवेदक जिनका पंजीयन 2 वर्ष की अवधि में पुनरावलोकन (Review) किया हुआ हो से निर्धारित प्रपत्र मे ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.jodhpurjda.org, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।
UBN No. :- JOD2425WSOB00210 TO JOD2425WSOB00219
राज.संवाद/सी/24/7012 अधिशाषी अभियंता

जनरल अमर सिंह कानोता कप टूर्नामेंट : जयपुर ने आरपीसी को और कानोता पोलो / स्पेक्ट्रम ने वी पोलो को हराया

जयपुर, 25 अक्टूबर। जनरल अमर सिंह कानोता कप (04 गोल) टूर्नामेंट में जयपुर ने आरपीसी को 6.1/2-8 से हराया। ड्सरे मैच में कानोता पोलो/स्पेक्ट्रम पोलो ने वी पोलो को 7-8 से हराया। जयपुर टीम की ओर से महाराज पदमनाभ सिंह ने विरोधी टीम पर लगातार 4 गोल कर अपनी टीम की जीत पक्की की। वाट्सन ने भी 4 गोल किये वही आरपीसी की ओर से सिद्धांत सिंह ने 1, एलेन ओर रणशेय ने 2-2 गोल किये। कानोता पोलो/स्पेक्ट्रम पोलो की ओर से प्रताप सिंह ने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए 3 गोल किये, मजीनी ने आज फिर वी पोलो पर ताबड़तोड़ खेल खेलते हुए 5 गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई वहीँ वी पोलो की ओर से सराहनीय खेल दिखाते हुए निमित मेहता ने 4 गोल किये लेकिन अपनी टीम को हार से नही बचा सके। इनके अलावा अंगद कलान ने भी 2, यनजोंन ने भी 1 गोल किया।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024 के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे मो. शमी, बंगाल के लिए खेल सकते हैं रणजी ट्रॉफी

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। मोहम्मद शमी पिछले साल नवंबर में 50 ओवर के विश्व कप फाइनल के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। उम्मीद की जा रही है थी कि वह अगले महीने टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा सकते हैं लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए दो मैच खेल सकते हैं। बंगाल टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि 34 वर्षीय शमी क्रमशः राउंड 3 और 4 के मुकाबलों में खेलेंगे।मोहम्मद शमी 6 नवंबर से शुरू होने वाले कर्नाटक के खिलाफ मैच से पहले बेंगलुरु में बंगाल टी से जुड़ने की संभावना है। तेज गेंदबाज को इंदौर में मध्य प्रदेश के खिलाफ अगले मैच में भी खेले की उम्मीद है।

नोटिस सूचना वास्ते सर्वसाधारण
मैं अपने पक्षकार नूरजहां बेगम पत्नी स्व. निसार, इजहार हुसैन पुत्र निसार हुसैन, शमां नाज पुत्री निसार हुसैन, अफशा नाज पुत्री निसार हुसैन, हुमा खान पुत्री निसार हुसैन, रीमा पुत्री निसार हुसैन जातियान मुसलमान निवासीगण छबड़ा जिला बारां (राज.) की हिदायतानुसार निम्न आशय की सूचना नोटिस प्रेषित करता हूं।
यह कि मेरे पक्षकारान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नंबर 133/1380 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 135 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 137 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा कुल किता तीन कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा वाके माल छबड़ा जिला बारां (राज.) में स्थित है, को लेकर एक वाद न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय छबड़ा के यहां बउनवान नूरजहां बेगम वगैरहा बनाम मजहर हुसैन वगैरहा विचाराधीन है। उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसके प्रत्येक खसरा नंबर पर मेरे पक्षकारान का जन्मजात अधिकार है। वर्तमान में उक्त आराजी विवादित है। कोई भी व्यक्ति उक्त आराजी के किसी भी हिस्से को क्रय नहीं करें। यदि दौराने वाद उक्त आराजी के किसी हिस्से को कोई भी व्यक्ति क्रय करेगा तो ऐसा विक्रय सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 से प्रभावित होगा और ऐसा बेचान शुन्य होगा। ऐसी सूरत में यदि कोई व्यक्ति उक्त विवादित आराजी को क्रय करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
अत: आमजन को जर्ये नोटिस आगाह किया जाता है कि उक्त नोटिस में वर्णित विवादित आराजी को कोई भी व्यक्ति वाद के निस्तारण तक क्रय नहीं करें।
स्थान : छबड़ा
दिनांक : 25.10.2024
भवदीय
राजेश भार्गव एडवोकेट
छबड़ा जिला बारां (राज.)

टैंक में डुबोकर हत्या की

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले में मां ने दो मासूम बेटियों को डिग्गी (पानी के टैंक) में डाल दिया। डूबने से बच्चियों की मौत हो गई। वहीं इसके बाद मां ने जहर पी लिया। जब इससे उसकी मौत नहीं हुई तो उसने कमरे में खुद को आग लगा ली, लेकिन देवर ने उसे बचा लिया। सुसाइड की कोशिश करने से पहले महिला ने भाई को फोन भी किया था।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2701 **विज्ञप्ति** दिनांक:-25.10.2024
सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी में स्थित कृषि भूमि योजना आदर्श नगर भूखण्ड संख्या 30 खसरा नं. 240 आवेदक/आवेदिका श्रीमती मोनिका विजयवर्गीय पत्नि श्री सत्य नारायण विजयवर्गीय निवासी 30, आर्दश नगर कुन्हाडी, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 4514 दिनांक 03.01.2007 को श्री कजोडमल विजयवर्गीय पुत्र श्री मूलचन्द विजयवर्गीय के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 20.05.2016 को हो चुकी है। पट्टाधारी द्वारा अपने जीवनकाल में रजि. वसीयतनामा दिनांक 17.04.2008 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है।
अत: श्रीमती मोनिका विजयवर्गीय पत्नि श्री सत्य नारायण विजयवर्गीय के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्रमांक-संक्षिप्त वि.सं.19/Exam/School Leet./RPSC/EP-1/2024-25 दिनांक- 25.10.2024
आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) के 24 विषयों के कुल 2202 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है-

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।
आवेदन अवधि	दिनांक 05.11.2024 से दिनांक 04.12.2024 रात्रि 12.00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

अन्य बिन्दु व सूचना-एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.-0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।
DIPR/C/______/2024 राम निवास मेहता, सचिव

गुंडागर्दी और पत्थरबाजी हमारी सरकार में नहीं चलेगी : मुख्यमंत्री भजनलाल

बीएपी ने सपने दिखाने और अशांति फैलाने का ही काम किया है : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाजपा नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया।

सलूंबर/डूंगरपुर, (निसं)। सलूंबर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नामांकन सभा की।

आयोजित सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहले सलूंबर और सराड़ा में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी। सड़कों पर किस तरह की स्थिति होती थी उसको हमने मजबूत किया और इस तरह की घटनाएं हमारी सरकार ने रोकने का काम किया है। गुंडागर्दी और पत्थरबाजी हमारी सरकार में नहीं चलेगी। सीएम ने कहा कि मेरे पास सलूंबर के काम की बड़ी लिस्ट है। प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर प्रताप सर्किट बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। ये सब हमारे बजट में है। सरकार काम करेगी। सलूंबर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अमृतलाल मीणा के वायदे हम पूरे करेंगे। सीएम ने सबसे हाथ खड़े करवाए कि यहां से वे भाजपा को जीताएंगे। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा उम्मीदवार शांता मीणा को दुपट्टा पहनाया। सभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा आदि ने भी संबोधित किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार देर शाम को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीमलवाड़ा में चौरासी विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा उम्मीदवार कारीलाल ननोमा के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित किया और भाजपा के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस ओर बीएपी पर जमकर निशाना भी साधा। भाजपा नेताओं ने सीएम का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हीं तीर कमान भेट किया। इसके बाद नामांकन सभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संबोधित किया। मदन राठौड़ ने जनता से क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए भाजपा उम्मीदवार कारीलाल को जिताकर विधानसभा भेजने का आव्हान किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 70 साल से राज करने वाली कांग्रेस ओर पिछले दो बार से जीतने वाले बीएपी के नेताओं ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। बीएपी के नेताओं ने क्षेत्र में सपने दिखाने ओर अशांति फैलाने का ही काम किया है।

नगर निगम, कोटा दक्षिण-उत्तर
131 वां राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा
ड्रोन शो
रात्रि 7:00 बजे | प्रायोजक: कोटा विकास प्राधिकरण
गतका कार्यक्रम
रात्रि 7:30 बजे
पंजाबी नाइट
(परमीश वर्मा)
रात्रि 8:30 बजे | प्रायोजक: के.ई.डी.एल.
26 अक्टूबर 2024, शनिवार | विजयश्री रंगमंच, दशहरा मैदान, कोटा
गरिमामयी उपस्थिति
श्रीमती कल्पना देवी, माननीय विधायक, लाडपुरा
श्री मोतीलाल मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा राजस्थान
श्री राकेश जैन, जिलाध्यक्ष, भाजपा कोटा शहर
* आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं *
विनीत : विवेक राजवंशी, अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, मेला समिति
नगर निगम दक्षिण-उत्तर परिवार

Phone No.-02992-294622, Email ID eedist.jsl.phed@rajasthan.gov.in
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिलाखण्ड जैसलमेर
क्रमांक/अधि.अभि./निविदा/जैसल/2024-25/1715-28 दिनांक- 22.10.2024
बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या-8(1-3)/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जन स्वा. अभि. विभाग राजस्थान के अन्तर्गत इस खण्ड के अधीन विभिन्न सिविल एवं अन्य कार्यो हेतु अनुमानित लागत रु. 35.12 लाख के कुल 3 कार्य हेतु राजस्थान सरकार के अधीन पंजीकरण नियमों के तहत उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं दिनांक 04.11.2024 सायं 06.00 बजे तक डॉउनलोड की जाकर दिनांक 05.11.2024 को सायं 1.00 बजे बिड शुल्क, ई-प्रक्रिया शुल्क, धरोहर राशि का चालान भौतिक रूप से इार्यालय में जमा कर उसी दिनांक 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से संबंधित विवरण DIPR की वेबसाईट WWW.dipronline.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता हैं। निविदा संख्या 8(1-3)2024-25 का विभागीय वेबसाइट www.sppp.raj.nic.in से प्राप्त NIB NO.-PHE2425A2621) UBN NO. निम्न प्रकार से है- PHE2425WSOB05711, PHE2425WSOB05712, PHE2425WSOB05713
(प्रेमा राम) अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
DIPR/C/10481/2024 जिला खण्ड-जैसलमेर

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org
क्रमांक :- स्टेशनरी/2024-25/14951 दिनांक :- 23/10/2024
निविदा सूचना संख्या 03/2024-25/स्टेशनरी
नगर निगम बीकानेर द्वारा डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफी व विडियोग्राफी का कार्य करने के इच्छुक सम्भरणकर्त्ता जो कार्य करने/सामग्री सम्भरण करने के लिए अधिकृत/पंजीकृत हो से दरें निर्धारित निविदा प्रपत्र में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.ino http://sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।
अनुमानित लागत राशि :-12.00 लाख
UBN Number : DLB2425SLOB11149
राज.संवाद/सी/24/6985 आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No.:F-2(01)Acct/Contract/2024-25/147-149 Date: 23-10-2024
ई–निविदा सूचना संख्या : 40/2024–25
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा कार्यो की कुल लागत	:	रूपये 432.05 लाख (11 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	:	25–10–2024 को प्रातः 10.00 बजे से 06–11–2024 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	25–10–2024 को प्रातः 10.00 बजे से 06–11–2024 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	07–11–2024 को प्रातः 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN : ITU2425WSOB00330 TO ITU2425WSOB00339
अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत
राज.संवाद/सी/24/7001 उदयपुर विकास प्राधिकरण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा
क्रमांक 3980 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.10.24
आवास संख्या 2-ज-18(ए) केशवपुरा कोटा का आवंटन मंडल द्वारा डालूराम पुत्र श्री कन्हैया लाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री निरंजन शर्मा पुत्र श्री सदाशिव के नाम दिनांक 20.02.1995 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री निरंजन शर्मा पुत्र श्री सदाशिव के नाम दिनांक 20.02.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री निरंजन शर्मा पुत्र श्री सदाशिव द्वारा उक्त आवास का दान जरिये दान पत्र आलेखित कर दिनांक 14.08.2023 को पुत्रवधु श्रीमती प्रीति कंवर पत्नी श्री भूपेश सिंह को किया गया। श्रीमती प्रीति कंवर पत्नी श्री भूपेश सिंह का नाम दिनांक 14.05.2024 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती प्रीति कंवर पत्नी श्री भूपेश सिंह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 19.07.2024 को श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री हरि राम जैन को किया गया। श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री हरि राम जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-ज-18(ए) केशवपुरा कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।
अत: इस आवास के मंडल अभिलेख में श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री हरि राम जैन का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री हरि राम जैन का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री हरि राम जैन का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा
क्रमांक 3977 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.10.24
आवास संख्या 2/12 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री घासीलाल पुत्र श्री चतुभुर्ज नामा को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री प्रमोद सिंह चौहान पुत्र श्री राजबहादुर सिंह चौहान के नाम दिनांक 09.04.2010 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री प्रमोद सिंह चौहान पुत्र श्री राजबहादुर सिंह चौहान के नाम दिनांक 23.08.2010 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री प्रमोद सिंह चौहान पुत्र श्री राजबहादुर सिंह चौहान द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 12.08.2013 को श्री महेश सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल सोलंकी को किया गया। श्री महेश सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल सोलंकी का नाम दिनांक 17.05.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री महेश सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल सोलंकी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 25.05.2024 को श्रीमती शिल्पा कसेरा पत्नी श्री दीपक भारद्वाज को किया गया। श्रीमती शिल्पा कसेरा पत्नी श्री दीपक भारद्वाज द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2/12 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।
अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती शिल्पा कसेरा पत्नी श्री दीपक भारद्वाज का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती शिल्पा कसेरा पत्नी श्री दीपक भारद्वाज का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती शिल्पा कसेरा पत्नी श्री दीपक भारद्वाज के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

डॉ. सतीश पूनिया ने महारावल चैतन्यराज सिंह से मुलाकात की

डॉ. पूनिया ने चैतन्यराज सिंह को पीएम मोदी पर लिखित पुस्तक ''द रियल मोदी'' भेंट की

डॉ. सतीश पूनियां ने जैसलमेर प्रवास पर महारावल चैतन्यराज सिंह को पुस्तक भेंट की।

जैसलमेर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने जैसलमेर प्रवास पर महारावल चैतन्यराज सिंह के साथ मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित पुस्तक ''द रियल मोदी'' भेंट। वहीं राजस्थान सीनियर मैन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने पर फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

जानकारी के अनुसार सतीश पूनिया ने भाजपा जिला कार्यालय जैसलमेर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर पूनिया ने कार्यालय में सदस्यता अभियान की कार्यशाला को संबोधित कर सदस्यता अभियान को बूथ, मंडल स्तर तक मजबूती से पहुंचाने का आव्हान किया, जिससे पूरे प्रदेश का देशभर में सदस्यता में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन सकेगा, यह कार्य पार्टी के कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पूंजी से संभव कर दिखाएंगे।

पूनियां की संगठन की मजबूती और जिले के विकास कार्यों को लेकर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सकारात्मक चर्चा हुई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा, विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह, नाचना ठाकुर विक्रम सिंह, जिला महामंत्री सवाई सिंह गोगली, जिला महामंत्री सुशील व्यास, पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी, मनोहर सिंह, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा कादर बक्स, नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित, पदम सिंह पूनमनगर, सुरेंद्र सिंह बडोडागांव, रघुवीरसिंह मंधा इत्यादि सहित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसलमेर में सतीश पूनियां ने भाजपा पूर्व जिला महामंत्री एवं युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष दलपत मेघवाल के दुःखद निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिवारजनों को ढांढस बंधाया। पूनियां ने भाजपा नेता एवं पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी के निवास पर पहुंचकर उनकी माताजी नैनू देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कृषि अनुसंधान केन्द्र
(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)
दाहोद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
Mo. No. 8112207969 / 9414389929 Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com, Visit us : www.mpuat.ac.in
क्रमांक : एफ( )/कृअके/2024-25/118-24 दिनांक 22.10.2024
निविदा सूचना (2024-25)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य/कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 08.11.2024 प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदायें उसी दिन दोपहर 11.30 बजे तक जमा की जाकर मध्यान्ह् 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, बोरवट फार्म पर मक्का परियोजना में कृषि कार्य।	390250/-	8000/-	500/-

संभागीय निदेशक अनुसंधान

हमारी सरकार ने किसानों का दुख-दर्द समझा है-भजनलाल

खींवसर में भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा की नामांकन सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया

खींवसर, 25 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के दु:ख-दर्द को समझती है तथा किसानों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि से लेकर गेंहूँ की एम.एस.पी. तक में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब सरकार मूँग की एम.एस.पी. पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पेयजल एवं सिंचाई में पानी की महत्ता को समझते हुए हमने सरकार में आते ही ई.आर.सी.पी. और यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की विरोधी है, क्योंकि इनके नेताओं ने तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यमुना जल समझौते को निरस्त करने का वादा किया था।

शर्मा शुक्रवार को खींवसर में विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लूट और झूठ की पार्टी है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किये गये किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, जबकि हमने मात्र 10 महीने में ही संकल्प पत्र में किए गए 50 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं तथा आगे भी एक-एक वादे को पूरा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपरलीक मामलों से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ था। हम युवाओं की आंखों में आंसू लाने वाले अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। सरकार द्वारा इन मामलों में अब तक 200 से भी अधिक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाने के लिए हमने दो साल का भर्ती कलेण्डर परीक्षा परिणामों की तारीख सहित निकाला है। हमारी सरकार युवाओं को पांच वर्ष में चार लाख सरकारी नौकरी देगी, जिनमें से पहले साल में ही हम एक लाख नौकरी दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागौर राजस्थान की हृदयस्थली है। यहां के जवान-किसान मजबूती से काम करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम किसानों को सुचारू रूप से पर्याप्त बिजली देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख 24 हजार करोड़ के एम.ओ.यू. किए हैं।

मुख्यमंत्री ने आमजन से रेवंत राम डांगा को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, उद्योग राज्यमंत्री के.के. बिश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री मंजू बाघमार, किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी सहित, विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने शुक्रवार को खींवसर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित किया तथा भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आव्हान किया।

- **उन्होंने जनसभा में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने मात्र 10 महीने में 50 प्रतिशत वादे पूरे किये हैं। आगे भी एक-एक वादे को पूरा किया जायेगा।**
- **नामांकन सभा में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्य के मंत्री गजेन्द्र खींवसर, झाबर सिंह खर्रा, सुरेश रावत, के.के. बिश्नोई, जोगेश्वर गर्ग, मंजू बाघमार, किसान आयोग के अध्यक्ष बी.आर. चौधरी, विधायक व पदाधिकारी उपस्थित थे।**

प्रैस काउन्सिल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने असंतोष जताया तथा फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी द्वारा तैयार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन्डैक्स की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, "रैंकिंग की पद्धति संदिग्ध है तथा पी.सी.आई. ने पहले भी इन रिपोर्ट्स की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था।"

देसाई ने कहा कि इंडियन प्रेस फ्रीडम एनुअल रिपोर्ट, जिसे इंडियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन इनिशिएटिव ने बनाया, की प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा के चुनाव नतीजों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिव सेना को धीरे-धीरे दरकिनार करती जा रही है, क्योंकि उसका मानना है कि केन्द्र सरकार तथा भाजपा नेतृत्व के समर्थन और सहारे के बावजूद शिंदे, उद्धव ठाकरे को कमज़ोर करने में असफल रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस, जिसने 2019 में केवल एक सीट जीती थी, ने इस बार काफी आगे बढ़ते हुए, 13 सीटें जीती थीं।

टिकट-वितरण तथा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भाजपा नेता देवेन्द्र फड़नवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहा तनाव पहले ही सामने आ चुका है। भाजपा और आर.एस.एस. यह सुनिश्चित करने के लिये अथक प्रयास कर रही हैं कि अगर भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, तो वह मुख्यमंत्री पद के लिये अपना प्रत्याशी आगे ला सकती है। लेकिन ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती कि भाजपा अपने बल पर सरकार बना लेगी। चुनावों के बाद, शिंदे तथा पवार दोनों का ही भविष्य चुनाव-परिणामों पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र में, भाजपा तथा शिंदे गुट ने चुनाव दो माह विलम्ब से कराने की इच्छा जाहिर की थी, ताकि "लाड़ली बहना योजना" को क्रियान्वित किया जा सके, लेकिन महायुति गठबंधन इसका पूरा लाभ लेने में विफल रहा है। हरियाणा की सफलता के बाद, भाजपा ने सीट-वितरण संबंधी वार्ताओं में शिंदे और अजित पवार पर बढ़त हासिल करने की व्यवस्था कर ली है।

महाराष्ट्र में, मराठा आरक्षण भाजपा के लिये बड़ी महत्वपूर्ण बाधा बन गया है। मनोज जरांगे पाटिल इस आंदोलन के नेता के रूप में उभरे हैं तथ कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिये हैं। ये प्रत्याशी दोनों ही गठबंधनों के वोट काट सकते हैं। पाटिल के समर्थकों का मानना है कि पाटिल भाजपा को हराने के लिये काम कर रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री फड़नवीस के कार्यकाल में, उनके आंदोलन को कमज़ोर करने के प्रयास किये गये थे।

'घर का जोगी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पोस्ट में लिखा था, "हान कांग की "वैजिटेरियन" मेरे बच्चे की स्कूल लाइब्रेरी में "टु बाय" (खरीदने) लिस्ट में है। हमारे बच्चे संभोग के ऐसे कामोत्तेजक वर्णन वाली किताब कैसे पढ़ सकते है?

पोस्ट लिखने वाली ने कहा कि वो स्कूल को इस संबंध में औपचारिक शिकायत करेगी। तथापि, कुछ लोगों का कहना है कि अपने बच्चों को विश्वभर में मान्यता प्राप्त किताब को पढ़ने से रोकना बेतुकी बात है। सिओल के एक हाई स्कूल के एक टीचर ने "द कोरिया हैरल्ड" को बताया "हमें गर्व होना चाहिए कि इस वर्ष का लिटरेचर का नोबल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखक को मिला है। वे साहित्य में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली इस क्षेत्र की पहली महिला हैं।"

केजरीवाल पर पद यात्रा के दौरान हमला

मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर गुंडों द्वारा हमला कराने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शुक्रवार को दिल्ली में एक रैली के दौरान हमला किया गया। आप ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि यह हमला भाजपा ने अपने गुंडों के माध्यम से कराया था। पार्टी ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के गुंडों को नहीं रोका। बता दें कि आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा से जुड़े लोगों ने रविंद केजरीवाल पर शुक्रवार की शाम पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में उनकी पदयात्रा के दौरान हमला किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के लोगों ने देखा है कि भाजपा की गंदी राजनीति कितनी गिर सकती है। उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल पर उनकी विकासपुरी पदयात्रा के दौरान भाजपा के गुंडों ने हमला किया था। भाजपा जानती है कि वह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती, इसलिए उन्होंने ऐसी गंदी राजनीति का सहारा लिया है और अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं।"

आतिशी ने आगे कहा, "पिछले दो वर्षों में, भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब वह जेल में थे, तो भाजपा ने 30 साल के मधुमेह से पीड़ित एक व्यक्ति को इंसुलिन देने से इनकार कर दिया। जब आप कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें इंसुलिन मिला।

चूंकि भाजपा अब यह महसूस कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के उनके प्रयास सभी मोर्चों पर विफल हो गए हैं, इसीलिए उनकी पदयात्रा के दौरान उन पर जानलेवा हमले की योजना बनाई गई।

- **"आप" पार्टी का आरोप है कि शुक्रवार की शाम पश्चिम दिल्ली के विकास पुरी क्षेत्र में पद यात्रा के दौरान भाजपा के गुंडों ने अरविन्द केजरीवाल पर हमला किया तथा दिल्ली पुलिस ने गुंडों को नहीं रोका।**

विख्यात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वकालत करती थीं। उनके शैक्षिणक प्रयास आने वाली पीढ़ि यों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"

एडिशनल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आदेश पवन कुमार की जमानत याचिका पर दिया।

अधिवक्ता रविन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत को बताया गया था कि उसने परिवादी पक्ष को राजीनामे के तौर पर 34 लाख रुपए एडिशनल एस.पी. सुरेश खींची की मौजूदगी में दिए थे, जबकि वे मामले में आई.ओ. भी नहीं थे। जिस पर अदालत ने एडिशनल एस.पी. खींची को उपस्थित होकर उनकी भूमिका बताने के लिए कहा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। उनकी जगह एस.आई. संतराम ने पेश होकर कहा कि खींची मेघालय में प्रशिक्षण हेतु व्यस्त हैं। इसके साथ ही डी.जी.पी. ऑफिस से जारी एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि एफ.आई.आर. गंगापुर सिटी पुलिस थाने की है और उस समय खींची का परिवादी पक्ष से परिचय था।

उनकी ओर से व्यक्तिगत हैसियत से मध्यस्थता की गई है और पदीय अधिकारों का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। दरअसल परिवादी स्कूल संचालक ने 2022 में आरोपी स्कूल लेखाकार पर रुपए गबन करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जून 2024 में गिरफ्तार कर लिया और वह तब से जेल में ही है। आरोपी का कहना था कि एडिशनल एस.पी. खींची के प्रभाव के चलते यह अनुचित कार्रवाई की गई और उससे जबरन राजीनामा करवाया गया, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

'विभागीय कार्यवाही ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता 6 नवंबर से पहले भारत लौट आएगा और तत्काल इसकी जानकारी विभाग को देगा। इसके अलावा, वह सिंगापुर को छोड़कर किसी अन्य देश की यात्रा नहीं करेगा।

याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्यूमेंट्स लिमिटेड में अधिकारी है। उसने अपने सिंगापुर रहने वाले अपने बेटे से मिलने के लिए 26 सितंबर को प्रार्थना पत्र पेश कर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन विभाग ने उसके प्रार्थना पत्र पर काई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामला हाईकोर्ट में आने के बाद, अदालत ने विभाग को नोटिस जारी किए। उसकी विभाग को तामील होने के बाद, उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए और अदालत को जानकारी दी कि विभागीय जांच लंबित होने के कारण उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे विदेश में रह रहे बेटे से मिलने का मौलिक अधिकार है। इसलिए उसे विदेश जाने की मंजूरी दी जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सशर्त विदेश जाने की अनुमति दी है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908